लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 5–सोमवार, 29 मई, 1967/8 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 5–Monday, May 29, 1967/Jyaistha 8, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
121	दो अमरीकी सीनेटरों द्वारा अमरीकी कांग्रेस को प्रतिवेदन — Report to US Congress by Two US Senators	621–624
122	भारत-पाक संघर्ष के दौरान हुई गलतियां — Shortcomings Noticed during Indo-Pak. Conflict	624–628
123	जैसलमेर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घुसपैठ — Intrusion by Pak. Soldiers in Jaisalmer	628–629
125	यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फार इन्टर-नेशनल डवल्पमेंट — United States Agency for International Development	629–631
अ. पू. प्रश्न S. N. Q.		
2.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में हड़ताल — Strike in Trombay Fertilizer Factory	631–634

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. No.			
126	भारत को शस्त्रों के विक्रय पर संयुक्त रूप से प्रतिबन्ध लगाना	Joint Limitation on sale of Arms to India	634–635
127	आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण का प्रभाव	Effects of Commercial Broadcast	635
128	पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Violation of Indian Air Space by Pakistan	635
129	परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb	636
130	बर्मा से स्वदेश लौटे हुए भारतीयों को मुआवजे का भुगतान	Compensation to be paid to Indian repatriates from Burma	636–637
131	मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का लगाया जाना	Ins talation of Medium Wave Transmitter	637
132	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	637–638
133	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं और बौद्धों का प्रव्रजन	Migration of Hindus and Buddhist from East Pakistan	638
134	छोटे समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota for Small Newspapers	638–639
135	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Campaign by Pakistan	639–640

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तां. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
136 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शान्ति बनाये रखने के लिये कार्यवाही	U. N. Peace keeping Operations	640
137 डा. कोनराड आडेनावर की अन्त्येष्टि	Funderal of Dr.Konrad Adenauer	640–641
138 विदेश मन्त्री तथा विदेश सचिव द्वारा विदेशों का दौरा	Visits abroad Foreign Minister and Foreign Secretary ..	641-642
139 राष्ट्रीय छात्र सेना का अनिवार्य प्रशिक्षण	Compulsory N.C.C. Training ..	642–643
140 अखबारी कागज के बारे में नीति	Newsprint Policy	643
141 भारत को अमरीकी हथियारों का सम्भरण	US Arms Supply to India ..	643–644
142 खान अब्दुल गफ्फार खां को निमन्त्रण	Invitation to Khan Abdul Ghaffar Khan to visit to India ..	644–645
143 राजदूतों के पदों पर नियुक्तियां	Appointments to Ambassadorial Posts	645
144 एच. एफ -24 जैट विमान	HF-24 Jets	645–646
145 चीन द्वारा कोलम्बो का उल्लंघन	Violation of Colombo proposals by China	646
146 पाकिस्तान द्वारा आण्विक बम का विस्फोट	Explosion of Nuclear Bomb by Pakistan	646–647
147 बर्मा सरकार के साथ बातचीत	Negotiations with Burmese Government question	647
148 पाकिस्तान को टर्की का समर्थन	Turkish Support to Pakistan ..	647–648
149 वियतनाम में सैनिक कार्यवाही	Military Operations in Vietnam	648
150 भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Violations of Indian Air Space ..	648–649
अतां. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
701 बाल फिल्म सोसाइटी	Children's Film Society	649–650
702 फिल्मों का आयात	Import of Films	650
703 भारत के समाचार पत्र	Newspapers in India	650–651
704 ट्रांसमिशन रिसीवर	Transmission Receivers	651
705 विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Foreign countries	652
706 राष्ट्रीय छात्रसेना दल	N. C. C.	652
707 आकाशवाणी में मकैनिक	Mechanics in AIR	652–653
708 आकाशवाणी में मकैनिकों की पदोन्नति	Promotion of Mechanics in AIR	653–654
709 आकाशवाणी के तीसरी श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Class III Technical Staff of AIR ..	654
710 आकाशवाणी में मैकेनिक	Mechanics in AIR	654–655
711 आकाशवाणी में कार्यभारित कर्मचारी	Work charged Staff in A I R. ..	655
712 राजस्थान में पाकिस्तानी अपराधियों की गतिविधियाँ	Activities of Pak Criminals in Rajasthan	655–656
713 त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा घुसपैठ	Intrusion by East Pakistan Armed Forces in Tripura	656–657

अता. प्र. संख्या. U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
714	अदन राष्ट्रवादियों की विदेश में प्रस्तावित सरकार	Government in exile proposed by Aden Nationalists	657–658
715	पारपत्र (पासपोर्ट)	Passports	658
716	अमरीकी दूतावासों में भारतीय	Indians in US Diplomatic Missions	658–659
717	पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजन	Indian National Detained in Pakistan	659
718	सद्भावना मिशन	Goodwill Missions	659
719	पांच वर्षों से विदेशों में रह रहे वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारी	Officials of External Affairs Ministry Staying Abroad for Five Years	660
720	दिल्ली में जवानों के स्मारक	Memorial for Jawans in Delhi ..	660
721	यूनान की नई सरकार को मान्यता	Recognition of new Government in Greece	660–661
722	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के अध्यक्षों के रूप में राजनयिक अधिकारी तथा सार्वजनिक नेता	Diplomats and Publicmen as Heads of Indian Missions Abroad	661
723	लन्दन में भारतीय उच्च आयोग	Indian High Commission in London	661–662
724	आयुध कारखानों में प्रोत्साहन बोनस योजना	Incentive Bonus Scheme in Ordinance Factories	662
725	हिमालय क्षेत्र में यूरेनियम के निक्षेप	Uranium Deposits in Himalayan Region	662–663
726	शैक्षिक टेलीविजन	Educational Television	663
727	भारत में विदेशी संवाददाता	Foreign Correspondents in India	663
728	1965 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति प्राप्त अथवा लापता सैनिकों तथा असैनिकों के परिवारों को सहायता	Assistance to Families of civilian and Military personnel killed or missing during 1965 Indo-Pak. Conflied	664
729	प्रधान मंत्री की श्रीलंका की यात्रा	Prime Minister's visit to Ceylon question	664
730	पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी जर्मनी से टैंकों की खरीददारी	Purchase of Tanks by Pakistan from West Germany	664–665
731	अपंग सैनिकों के लिये आश्रम (होम)	Homes for Invalid Ex-Servicemen	665
732	पालम हवाई अड्डे से टायर और ट्यूबों की चोरी	Theft of Tyres and Tubes from Palam Airport	665
733	नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Nagas	666–667
734	रोडेशिया	Rhodesia	667
735	भारतीय राजनयिकों का पैकिंग में स्वागत समारोह से उठकर चला जाना	Walk out by Indian diplomats a reception in Peking	667–668
736	सैनिकों को उपदान	Gratuity to Soldiers	668
737	अग्र क्षेत्रों में सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिये क्वार्टर	Family Quarters for Armed Forces personnel in Forward Areas ..	668–669
738	बिहार में सहायता कार्यों के लिये सेना की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of Services of Army in Bihar for Relief Operation	669

739	समाचार पत्रों में विज्ञापन	Advertisements in Newspapers ..	669-670
740	ढाका में भारतीय उच्च आयुक्त	Indian High Commissioner in Dacca	670
741	सैनिक आवास बस्तियाँ	Sainik Housing Colonies	670-671
743	पाकिस्तान के रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propaganda by Pak ..	671
744	परमाणु इंजीनियरी	Atomic Engineering	671-672
745	इस्लामी देशों का आर्थिक गुट	Islamic Economic Bloc	672
746	प्रतिरक्षा पर व्यय	Defence Expenditure	673
747	भारतीय नौसैना के भण्डारों में सामान देने की प्रणाली	Indian Navy Stores Provisioning System	673-674
748	उड़ीसा में सैनिक स्कूल	Sainik School in Orissa	674
749	भूतान में भारतीय	Indians in Bhutan	674
750	हिन्दी समाचार कक्ष	Hindi News Room	675
751	किट्टूर (मैसूर) में सैनिक स्कूल	Sainik School at Kittur (Mysore)	675
753	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड, दरभंगा	Soldiers' Sallors' and Airmen's Board, Dharbhanga	675-676
754	ती बाड़ी के सम्बन्ध में रेडियो कार्यक्रम	Radio Programmes on Cultivation	676
755	रक्सौल में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station at Raxaul	676-677
756	विदेशों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार	Correspondence with Foreign Countries in Hindi	677
757	सैनिक कर्मचारियों द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Books of Military Personnel	677
758	सहकारी आधार पर समाचार पत्र	Co-operative Newspapers ..	678
759	सैनिक कृषि फार्म, काशीपुर	Military Agriculture Farm, Kashipur	678
760	टट्टू प्रजनन केन्द्र, बाबूगढ़ (उत्तर प्रदेश)	Pony Breeding Centre, Babugarh U. P.	679
761	आकाशवाणी से संसद सदस्यों की वार्तायें	Broadcast by M.Ps. ..	679
762	भारत से ब्रिटेन जाने वाले भारतीय लोगों के बारे में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ बातचीत	Talks with British High Commissioner about Indian Immigrants	679
763	पूर्वी पाकिस्तान नागालैंड नेफा ब्लाक के बारे में सी. आई. ए. की योजना	CIA Scheme re : East Pakistan Nagaland NEFA Bloc ..	680
765	बड़ौदा में भूमि का अर्जन	Acquisition of land at Baroda ..	680-681
766	अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच तनाव	Tension between Arab Nations and Israel	681
767	गोहाटी (आसाम) के लिये अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitter for Gauhati (ASSAM)	681
768	नेपाल का भूमि सुधार कानून	Land Reform Law of Nepal ..	682

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS – Contd.	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	682–686
पश्चिमी बंगाल में घेराव के मामले में केन्द्रीय गृह-कार्य मन्त्री का हस्तक्षेप	Alleged interference by the Union Home Minister in regard to gharaos in West Bengal ..	682–686
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	682
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	682
मन्त्रियों के बिड़ला बन्धुओं से वेतन पाने के आरोप के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377 re. Allegations against Ministers being in pay of the Birlas ..	686
विशेषाधिकार समिति के	Committee of Privilege ..	686–689
पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. First Report of ..	686–689
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	686–687
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	687–688
श्री आ. ना. मुल्ला	Snri A. N. Mulla	688
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	• 688
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ..	688
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	688
रेलवे आय व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा (जारी)	Railway Budget 1967-68–General icusssion (Contd.)	689–700
श्री राजाराम	Shri Rajaram ..	689–690
श्री बिश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	690–691
श्री जि. मो. बिस्वास	Shri J. M. Biswas	691–693
श्री रा. बरूआ	Shri R. Barua ..	693–694
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanatham	695–696
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	696
श्री जोर्ज फरनेंन्डीज	Shri George Fernandes ..	696–697
श्री विमला कान्ति घोष	Shri Bimalkanti Ghosh	697
श्री ज्योतिर्मय वसु	Shri Jyotirmoy Basu	697–699
श्री श्रद्धाकार सूपकार	Shri Sradhakar Supakar ..	699–700
श्री शिवप्पा	Shri N, Shivappa	700
पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. Supply of US Arms to Pakistan	701–704
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	701–702
श्री कंवरलाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta ..	702
श्री कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnam morthi	702
श्री दा. च. शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री पें वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasummaiah	702
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	703
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla ..	703–704

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 29 मई, 1967/8 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Monday, May 29, 1967/Jyaistha 8, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दो अमरीकी सीनेटरों द्वारा अमरीकी कांग्रेस को प्रतिवेदन

+

†*121. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री पी० एम० सईद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स्वैल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीनेटर गेल मैंक्गी और फ्रैंक ई० मौस द्वारा केन्द्रीय तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के उनके हाल के अध्ययन मिशन के बाद अमरीकी कांग्रेस को दिये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) क्या उनके प्रतिवेदन में उनके द्वारा भारत पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के प्रति अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) : जी हां। भारत के कुछ विषयों के बारे में प्रतिवेदन में कुछ आलोचनात्मक विचार व्यक्त किये गये हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं परन्तु हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि यह निरुत्साह करने के लिए हैं। फिर भी यह अमरीकी सरकार का सरकारी प्रतिवेदन नहीं है और इस कारण उससे विरोध प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri George Fernandes: The clarifications about the acts of American Government are made by the U. S. Ambassador in India or by U. S. newspapers here such as American Reporter. Similarly we have our Ambassador in U. S. A. Does he too make such clarifications ?

श्री मु० क० चागला : यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे राजदूत ने इन अमरीकी सेनेटरों द्वारा उत्पन्न की गलत धारणाओं का खंडन नहीं किया । परन्तु अमरीकी समाचार पत्रों में ऐसे खंडन छापना बहुत कठिन है । उन में ऐसे खंडन न छपने का यह अर्थ नहीं कि हमने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया ।

Shri George Fernandes: The American Government before permitting people to visit U. S. A. ascertains their political views. Will our Government too consider as to what type of people should be permitted to visit India ?

श्री मु० का० चागला : किसी भी व्यक्ति को भारत यात्रा करने की अनुमति देने से पूर्व गृह-कार्य मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद ही उसे वीजा दिया जाता है । यह बात सबके लिए लागू है चाहे वह अमरीकी हो अथवा कोई और ।

श्री जे० एच० पटेल : ने कनाड़ी भाषा में एक प्रश्न पूछा ।

Shri George Fernandes : He has asked whether Government is considering the question of giving them some awards ?

श्री मु० क० चागला : हम उन्हें कोई पुरस्कार देने का विचार नहीं रखते ।

Shri K. N. Tiwary : I have a point of order to raise. Whether such translation by other members in respect of unapproved languages will be permitted during Question Hour also ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का समाधान तो सारे सदन को करना है । परन्तु इसमें समय बहुत नष्ट होगा । यदि वे सदस्य भी दूसरी भाषाओं में प्रश्न पूछने लगें जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो ऐसा करके वे सदन का तथा अपना समय नष्ट करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : We have decided about the simultaneous arrangement in other languages too. What has happened to that ?

अध्यक्ष महोदय : सचिवालय इसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि यह शीघ्र हो गया तो ।

श्री मधु लिमये अब अपना प्रश्न पूछें ।

Shri Madhu Limaye : Whether the staff of our Embassy in U.S.A. develop personal contact with the Senators and members of the House of Representatives in U. S. A. and explain our stand to them and whether they send a report about it to the Government ?

श्री मु० का० चागला : जी हां, ऐसा किया जाता है और उसकी रिपोर्ट भी भेजते हैं । इस मामले में भी रिपोर्ट आई है परन्तु उसका यहां बताना उचित नहीं है क्योंकि यह एक निजी बात चीत है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन सेनेटरों की यह निजी यात्रा थी अथवा उन्हें वहां की संसद ने भेजा और उन्होंने संसद को उसकी रिपोर्ट दी ? क्या यह बात देखी है कि उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि यही उचित समय है कि भारत पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक तथा आर्थिक दबाव डाले जा सकते हैं ? यदि ऐसा है तो क्या यह बहुत आपत्तिजनक नहीं है और इसका हमें कूटनीतिज्ञ तरीकों से विरोध करना चाहिए ? क्या ऐसी कोई कार्यवाही की गई ओर यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री मु० क० चागला : यह सरकारी प्रतिनिधि मंडल नहीं था और यह बिल्कुल ऐसे हैं कि हमारे दो संसद सदस्य अमरीका जायें और अमरीका के बारे में अपने विचार यहां व्यक्त करें। यदि अमरीकी सरकार हमारे किसी संसद सदस्यों के वक्तव्यों पर आपत्ति करें तो हम भी करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो रिपोर्ट उन्होंने अमरीकी संसद को दी है। वह कोई साधारण वक्तव्य नहीं है।

श्री मु० का० चागला : मान लीजिये कि हमारे दो सदस्य भी ऐसे ही किसी यात्रा पर जाते हैं और उसकी रिपोर्ट संसद को देते हैं तो क्या इसके बारे में अमरीकी सरकार का कोई विरोध पत्र स्वीकार करेंगे। यह तो संसद का ही अधिकार है। यही स्थिति इसके बारे में भी है।

Shri K. N. Tiwary : What arrangements have been made by the Government to contradict such reports and give true facts for the public opinion there ?

श्री मु० क० चागला : इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री स्वैल : इन सेनेटरों की रिपोर्ट के साथ साथ अमरीका ने भारत और पाकिस्तान को फाल्तु सैनिक सामान सप्लाई करना फिर आरम्भ कर दिया। क्या कारण है कि हम इतना शोर मचाते हैं परन्तु अमरीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे समझते हैं कि दस वर्ष तक हमें चीन की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। क्या कारण है कि हम अमरीका को अपने केस की सत्यता से प्रभावित नहीं कर पाये।

श्री मु० क० चागला : इन सेनेटरों ने जो रिपोर्ट दी है उसके कुछ भागों से हमें सख्त आपत्ति है। जहां तक अमरीकी जनता को, हमें अपनी जानकारी देने का सम्बन्ध है तो उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी : क्योंकि यह रिपोर्ट अमरीकी संसद की प्रस्तुत की गई इसलिए यह अर्द्ध--सरकारी हो गई। फिर क्या कारण है कि सरकार अपने दूतावास के द्वारा क्यों नहीं इसका विरोध प्रकट करती ?

श्री मु० क० चागला : एक प्रतिनिधि मंडल तो सरकार द्वारा भेजा जाता है और वह सरकारी होता है और एक यह दल था। यदि सरकारी दल होता तो हम अवश्य आपत्ति करते। परन्तु संसद के सदस्यों की रिपोर्ट सरकारी नहीं है। यह शिष्टमंडल सरकारी शिष्ट-मंडल नहीं था।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय इन दो सेनेटरों के वक्तव्य से जो संसार में यह भ्रम फेल जायेगा कि सरकार राजनयिक स्तर पर विरोध प्रकट करने को भी तैयार नहीं है और उसके लिए नियमों का सहारा ले रही है जब कि वह हमारे बारे में यह बात कह रहे हैं जो वास्तव में नहीं हैं।

श्री मु० क० चागला : उचित अवसरों पर हमने अमरीकी सरकार को विरोध प्रकट किया है परन्तु यह मामला सरकारी रूप से विरोध प्रकट करने का नहीं है।

श्री रंगा : क्या हम कुछ ऐसा इन्तजाम नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति यहां आवें वह हमारे आतिथ्य का दुरोपयोग न करें ? यदि वह मंत्रियों से यहां मिलें तो उन्हें मिलने से इन्कार कर देना चाहिए। आप जो भी वहाँ से आता है उसके लिये मिलने का द्वार खोल देते हैं।

श्री मु० क० चागला : हम ध्यान रखते हैं कि यहां कौन आता है। परन्तु यदि हम उनसे न मिलें तो फिर यह आरोप लगाया जाता है कि हम उनसे मिलते नहीं हैं।

Shri Sheo Narain : Were these not responsible senators who came here and what action was taken by the Government for defaming us ?

श्री म० क० चागला : यह दो सेनेटर बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

भारत–पाक संघर्ष के दौरान हुई गलतियां

* **122. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले भारत--पाक संघर्ष के दौरान हमारी सैनिक दृष्टि से क्या कमियां थीं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की है; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और सरकार ने उन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : यद्यपि 1965 में भारत--पाक संघर्ष के दौरान जो अनुभव प्राप्त हुआ वह हमारी प्रशिक्षण प्रणाली की सुदृढता का परिचायक है, फिर भी हमारे संगठन, प्रशिक्षण, सामरिक संकल्पनाओं और सैनिक सामान की उपलब्धि आदि विषयों में ऐसा परिवर्तन लाने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया गया जो कि संघर्ष के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर लाना आवश्यक समझा गया था। विश्लेषण के परिणामों का मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप से पूरा उपयोग किया गया।

(1) रक्षा मदों को सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादन किए जाने के अतिरिक्त देश में ही उनके विकास और निर्माण के लिए उपाय किए गए।

(2) विभिन्न प्रशिक्षण सिब्बन्दियों में प्रशिक्षण व्यवस्था को, जहां तक जरूरी हुआ, पुनः ठीक से बनाया गया।

(3) थल सेना और वायु सेना के अफसरों के एक दल ने कमानों और प्रशिक्षण सिब्बन्दियों को संघर्ष में प्राप्त अनुभवों से अवगत कराया ।

(4) सेना के सम्पूर्ण ढांचे को और अच्छा बनाने के लिए संगठन की विस्तृत समीक्षा की गई ।

(5) अपनी फौज की फायर शक्ति को और अच्छा बनाने के लिए निर्णय लिए गए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There was a great scarcity of modern weapons with our Air Force and Land Forces of India during the Indo-Pakistan conflict. What is the loss we had to undergo on account of lack of such weapons ? What are the steps we have taken to make up that loss and how far have we succeeded in our efforts for the purpose ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो सच है कि पाकिस्तान की थल और वायु सेना के पास हमारे मुकाबले में आधुनिक उपकरण अधिक थे परन्तु हमारी थल और वायु सेना ने अपने शौर्य और रणकोशल के कारण पाकिस्तानी सेना के अच्छे दांत खट्टे किये । जहां हथियारों को प्राप्त करने का सम्बन्ध है, हमने अपने ही देश में हथियार बनाने शुरू कर दिये हैं तथा कुछ ऐसे आवश्यक हथियारों को बाहर से भी मंगाया गया है, जिनका मंगाया जाना सम्भव है । परन्तु सभा में इस मामले पर विस्तृत चर्चा करना वांछनीय नहीं है । हां, हमने अनेक प्रयत्न किये हैं और हमें अच्छी सफलता मिली है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the steps taken by the Government to make the Navy and Air Force more effective and to protect the border areas with the cities situated therein ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रतिरक्षा सम्बन्धी पूरी नीति ही इस प्रश्न में आ जाती है, जिसका उत्तर एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता । बजट पर चर्चा के दौरान इन सब बातों को लिया जा सकता है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह बताना लोक हित में नहीं है कि सीमान्त क्षेत्रों में क्या रक्षात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नाथ पाई : नेफा की पराजय से हम चाहते थे कि सरकार कुछ सबक सीखेगी और भविष्य में उन्हीं गलतियों को दोबारा न दुहराया जायेगा । परन्तु डेरा बाबा पुल के मोर्चे पर फिर एक ऐसे सैनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया जिसने अपना कर्त्तव्य निष्ठा-पूर्वक नहीं निभाया । क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि ऐसे अधिकारियों को जो साहसी और निष्ठावान नहीं हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मोर्चों की जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी ।

श्री स्वर्ण सिंह : नेफा की घटना से हमने बहुत कुछ सीखा है, और यही कारण है कि भारत--पाक संघर्ष के दौरान हमारी सेना को आशातीत सफलता मिली है । किसी सैनिक अधिकारी विशेष को किस स्थान पर नियुक्त करना है, इस बारे में सेना अध्यक्षों से परामर्श लिया जाता है, और उनके परामर्श से ही उनको नियुक्त किया जाता है । वैसे यह एक महत्व-

पूर्ण सुझाव है कि जिन अधिकारियों में शौर्य, साहस और पहल का माद्दा नहीं है उन्हें मोर्चे की कोई भी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिये। परन्तु उस अधिकारी विशेष के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पुनः चालू करने के अमरीकी निर्णय के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की युद्ध-शक्ति अधिक बढ़ जायेगी। पाकिस्तान की इस लिहाज से बराबरी करने के लिये सरकार ने किन देशों से हथियार पाने की कोशिश की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक सम्भव होता है हम यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के शस्त्र भंडार में क्या वृद्धि हो रही है। साथ ही हम इसके प्रति भी जागरूक हैं कि हमारी सैनिक तैयारी पिछड़ न जाये। यह कार्य निरन्तर चलता रहता है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : यह तो बात ठीक है कि हम आत्म-निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं; परन्तु आत्म-निर्भर होने में कुछ समय लगेगा। इस बीच अमरीका, रूस और ब्रिटेन के अतिरिक्त सैनिक सहायता लेने के लिये हमारी सरकार किन देशों से सम्पर्क कर रही है, क्योंकि यह सम्भावना है कि मौका पड़ने पर ये देश सहायता देने में असमर्थता प्रकट करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम विदेशों से सैनिक उपकरण मंगा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में अन्य देशों से भी सम्पर्क कर रहे हैं जहां से विभिन्न प्रकार का सैनिक माल हमें प्राप्त हो सके।

Shri Abdul Ghani Dar : What are those weapons Pakistan has acquired from U.S.A. and other sources after Indo-Pak conflict ? May I know whether we have got better equipments to weapons recently acquired by Pakistan ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि भारत-पाक संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने चीन सहित अनेक देशों से वायुयान, टैंक, बन्दूकें, छोटे हथियार आदि सैनिक सामान मंगाया है। वह फ्रांस से भी वायुयान तथा पनडुब्बियां मंगा रहा है। इस सम्बन्ध में हम भी यथा सम्भव कोशिश कर रहे हैं और उनके परिणाम संतोषजनक हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय पूर्वी पाकिस्तान से लगे भारतीय सीमान्त क्षेत्र में सड़क बनाने का काम अपने हाथ में लेगा, क्योंकि वहाँ पर संचार साधनों का काफी अभाव है।

श्री स्वर्ण सिंह : सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार साधन सुधारने के उद्देश्य से सड़कों को बनाने का काम सीमा सड़क विकास संगठन (बॉर्डर रोड्स डेवलप्मैंट आर्गेनाईजेशन) द्वारा किया जा रहा है। परन्तु भारत पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा, यह कार्य असैनिक निर्माण करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : During Indo-Pak conflict the greatest failure on our part had been the lack and inadequacy of the military intelligence. In view of that, I would like to know whether the Government have brought out certain specific changes in the intelligence structure of the military ?

श्री स्वर्णसिंह : गुप्तचर विभाग के पूरे ढांचे को पुनर्गठित कर दिया गया है और सूचना इकट्ठी करने के ढंगों में भी सुधार किया गया है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह दुख की बात है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय अभी तक प्रतिरक्षा के मामले में ब्रिटेन की विचार धारा और पद्धतियों से चिपटा हुआ है, जो आज के युग में पुरानी हो चुकी है । क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में कोई ऐसा नया सांचा ढालने का प्रयास किया है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो ?

श्री स्वर्णसिंह : यह सच है कि कुछ हद तक हमारी विचारधारा ब्रिटिश विचारधारा से मिलती है । परन्तु यह कहना कि हम उससे चिपटे हुए हैं, ठीक नहीं है। हम उसका भारतीय परिस्थितियों में पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं और उसे भारतीय बनाकर अपनाते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार बार-बार यह बताती है कि देश में सैनिक सामान का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर हो रहा है । इसके परिणामस्वरूप सैनिक सामान के आयात में क्या कुछ कमी हुई है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री स्वर्णसिंह : देशी उत्पादन की मात्रा बढ़ने से विदेशी माल पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आयात की मात्रा के बारे में एक निश्चित प्रश्न पूछा था ।

श्री स्वर्णसिंह : यह प्रश्न भारत-पाक संघर्ष तथा उससे जो शिक्षा ली गई उन सबके बारे में है । यदि माननीय सदस्य आयात सम्बन्धी आंकड़ों में रुचि रखते हैं वह कृपया एक पृथक प्रश्न भेज दें, जिसके उत्तर में उन्हें अपेक्षित जानकारी मिल जायेगी ।

श्री राम किशन : क्या पंजाब सरकार ने पश्चिमी कमान को हवाई अड्डों, छावनियों आदि के निर्माण तथा संचार साधनों के सुधार के लिये भारत-पाक संघर्ष से बाद में कुछ सुझाव भेजे हैं और खेमकरण तथा फजिलका की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वर्णसिंह : यह सच है कि कुछ सुझाव सरकार को मिले हैं तथा उनके अनुसार कुछ कार्यवाही भी की गई है । परन्तु जो काम किया जा चुका है, मैं उसका पूरा विवरण नहीं देना चाहता ।

Shri Balraj Madhok : It is a well-known fact that we met reverses particularly in areas where there were no means of communications which were habituated by the people of doubtful integrity and loyalty. May I know the steps taken by the Govt. to remove such people from the border areas of Jammu & Kashmir and to improve the means of communications in the border areas of Rajasthan ?

श्री स्वर्णसिंह : राजस्थान तथा सभी अन्य क्षेत्रों में संचार-साधन सुधारे जा रहे हैं । जहाँ तक सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आस्था का प्रश्न है, हमें इस प्रकार का सन्देह नहीं करना चहिये । सच तो यह है कि ऐसे प्रश्नों में साम्प्रदायिकता का पुट होता है ।

श्री बलराज मधोक : जो इसे साम्प्रदायिक कहते हैं वह स्वयं साम्प्रदायिक हैं । मैं एक राष्ट्रवादी के नाते बोल रहा हूँ । उन्हें भी एक राष्ट्रवादी के नाते ही बोलना चाहिए न कि एक साम्प्रदायिक के रूप में ।

~~प्रतिरक्षा मंत्री~~ (श्री स्वर्णसिंह) : वह उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितने कोई और। परन्तु जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार वह सीमा के पास रहने वाले लोगों की निष्ठा पर केवल धर्म के आधार पर शक कर रहे हैं। जन-समुदाय के स्थानान्तर को हमें सोचना भी नहीं चाहिए।

श्री रंगा : कुछ लोगों को उनके हित में तथा देश के हित में हस्तान्तर किया गया। मंत्री महोदय को ऐसे शब्द प्रयोग करके वाद-विवाद के वातावरण को खराब नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए।

Shri Abdul Ghani Dar : Shri Madhok should know that I have statistics about this.

Shri Ishaq Sambhati : This is an attack on the entire community. In Kashmir the person who gave information for the first time about infiltrators was Gujar Muslim Din Mohammed.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

जैसलमेर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घुसपैठ

+

***123. श्री भारतसिंह :** **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री प० ला० बारूपाल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अप्रैल, 1967 को 150 सशस्त्र पाकिस्तानी सैनिक जैसलमेर जिले में घुस आये और लूटमार की जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति घायल हो गये और बहुत सी सम्पत्ति लूट ली गई;

(ख) इसमें जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस तरह की कोई घटना नहीं हुई कि 10 अप्रैल 1967 को 150 हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक जैसलमेर जिले में घुस आए, कई लोगों को घायल कर दिया और संपत्ति लूट ले गए। हां, 9/10 अप्रैल 1967 की रात को पांच पाकिस्तानी उपद्रवी (जिनमें दो राइफलों से लैस थे, एक के पास बंदूक थी और दो लाठियां लिए हुए थे) नचाना में आए और 4 ऊंट हांक ले गए। वापस जाते हुए उन्होंने नचाना-बाहला सड़क पर लोक निर्माण विभाग के दो ट्रैक्टरों और दो ट्रकों को रोक लिया। उन्होंने ड्राइवरों को धमकाया और चारों गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए। उपर्युक्त घटना में जान की कोई हानि नहीं हुई।

भारतीय सीमांत अधिकारियों ने पाकिस्तानी सीमांत अधिकारियों के पास कड़ा विरोध-

पत्र भेजा था। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों को चुराए हुए ऊंटों में से दो ऊंट मिल गए और उन्होंने उन्हें भारतीय अधिकारियों को लौटा दिया। लोक निर्माण विभाग के श्रमिक शिविरों की देखभाल के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए हैं।

Shri Bharat Singh Chauhan : Whether it is a fact that on 10th April 1967, 150 armed Pakistani soldiers entered the Jaisalmer District ?

श्री मु० क० चागला : मैंने कहा है कि 10 अप्रैल 1967 को इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। परन्तु 9/10 अप्रैल की रात को कुछ पाकिस्तानी शरारती लोग राईफल, गन तथा लाठियों से लैस नाचाना में आये और 4 ऊंट उठा कर ले गये। उन्होंने लोक निर्माण के दो ट्रेक्टरों को रोका और उसके टायर पंचर कर दिये तथा उसके ड्राइवरों और अन्य लोगों को लाठियों से पीटा। इसमें जान की कोई हानि नहीं हुई।

Shri Madhu Limaye : Why is the External Affairs Minister replying to it ? Is Jaisalmer in a foreign country ? I highly object to it.

श्री मु० क० चागला : मैंने इसका उत्तर इसलिए दिया क्योंकि यह मेरे नाम पर दिया गया है।

Shri Bharat Singh Chauhan : Has some compensation been paid to the victims of the intruders or a scheme is under contemplation ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है क्योंकि इससे मेरे मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : जब भी इस प्रकार बलात प्रवेश होता है तो उसके पश्चात आक्रमण होता है। क्या सरकार इन घटनाओं को एक अलग घटना के रूप में देखती है अथवा यह समझती है कि शीघ्र ही पाकिस्तान से कोई आक्रमण होने वाला है ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह मानता हूँ कि ऐसी एक-एक घटनाओं के प्रभाव के कारण हमें चौकस रहना चाहिए।

श्री अमृत नाहाटा : मैं भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री मु० क० चागला : हम प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर की आशा वैदेशिक-कार्य मंत्री से नहीं रख सकते।

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इन्टर नेशनल डवल्पमेंट

+

***125. श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की "रेमपर्ट्स" नामक पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि सी० आई० ए० अपने कार्यकलापों के लिये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इन्टरनेशनल डेवेल्पमेंट का प्रयोग कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय दृष्टिकोण से इस समाचार में निहित अर्थों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि भारत में इस संगठन से कोई गलत कार्य करवाये जा रहे हैं तो उनको ऐसा करने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मो० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) : सरकार को मालूम है कि अमरीका तथा अन्य देशों में विद्यार्थियों के मामलों में केन्द्रीय आसूचना एजेंसी के कारनामों को लेकर "रेमपार्ट्स" नामक अमरीकी पत्रिका ने अपने लेख में यह बताया है कि कुछ व्यक्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उक्त एजेंसी के कारकुन हैं, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी में कभी न कभी काम कर चुके हैं। जैसा कि पहले घोषित किया जा चुका है, सरकार ने भारत में उक्त एजेंसी के धन का उपयोग करने के बारे में पूछ-ताछ शुरू कर दी है। अगर यह पता चला कि लोग अपने आधिकारिक पदों का लाभ उठाकर आपत्तिजनक कार्यवाईयां कर रहे हैं तो सरकार समुचित कार्यवाई करेगी ;

श्री राममूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के अधिकारी देख-भाल के बहाने उन परियोजनाओं में सरलता से जा सकते हैं जिनमें वे सहायता देते हैं तथा उन्हें काफी अवसर मिल सकता है कि वे वहां अपने खोटे कार्य करने के लिये अपने आदमी वहां स्थापित कर दें ? यदि हां तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सुझाव रखती है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में जो भी अमरीकी यहां इस कार्य में आये हैं वे सी० आई० ए० के एजेंट हैं। उनमें से बहुत कुछ निष्ठा से कार्य करते हैं।

श्री राममूर्ति : इन जासूसों की देख-भाल तथा इनके कार्यों को समाप्त करने के लिए क्या हमने भी अपना गुप्तचर विभाग उनकी देख-भाल के लिए नियुक्त किया है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे सहयोगी गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि सी० आई० ए० की कार्यवाहियों के बारे में एक जांच करा रहे हैं। हमें उसका इन्तजार करना चाहिए।

श्री अ० क० गोपालन : जो बातें सी० आई० ए० के बारे में "न्यूयार्क टाईम्स" तथा "रैम्पर्ट्स" में भारत तथा अन्य देशों के बारे में आई हैं क्या सरकार ने उनकी जांच की है। यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं तो ऐसा करने में कितना समय लगेगा तथा उसकी रिपोर्ट सदन के सामने कब आयेगी ?

श्री मु० क० चागला : मेरे सुझाव देने के कारण गृहकार्य मंत्री एक जांच करा रहे हैं। यह जांच अभी पूरी नहीं हुई और यह आदेश दिया गया है कि इसे शीघ्र पूरा किया जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उस जांच का कार्य क्षेत्र क्या है तथा क्या यह जांच सी० आई० ए० के सारे दृष्टिकोणों पर विचार करेगी तथा कब तक पूरी होगी ?

श्री मु० क० चागला : यह जांच गृहकार्य मंत्रालय करा रहा है। इसलिए मुझे उसका इतना पता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : भारतीय टेकनालोजी संस्था, कानपुर में सी० आई० ए० के

एजेंट कार्य कर रहे हैं तथा चुनाव से पहले उन्होंने वहां के अध्यापकों, वकीलों आदि से पूछा कि उन्होंने किसे मत दिया तथा वे 1972 में किस दल को मत देंगे। यह आपत्तिजनक परिपत्र है तथा सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री मु० क० चागला : यह सूचना तथा और भी जो बहुमूल्य सूचना हो वह गृहकार्य मंत्री के पास भेजनी चाहिए।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि उन प्रतिवेदनों का झुकाव किस ओर था ?

श्री मु० क० चागला : उनका यहां कहना जनहित में नहीं है।

श्री हेम बरुआ : रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी के समाचार पत्र "प्रावदा" ने लिखा है कि स्टालिन की बेटी स्वेतलाना का भारत से ले जाने में भी सी० आई० ए० के एजेंटों ने कार्य किया। यह भारत के कार्य में भाग लेना हुआ। क्या सरकार हमें प्रावदा के वक्तव्य पर कुछ बतायेगी ?

श्री मु० क० चागला : मैंने प्रावदा का वक्तव्य देखा है परन्तु स्वेतलाना के बारे में तो हम पहले ही यहां काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार ने श्रीमती भंडारनायके के वक्तव्य को पढ़ा है कि उनकी सरकार के पतन का कारण सी० आई० ए० थी तो क्या एशिया में इसके कार्य के बारे में सरकार ने अध्ययन किया है ?

श्री मु० क० चागला : इस देश की परिस्थितियों की जांच करना ही बहुत कठिन है फिर मैं लंका की परिस्थितियों की कैसे जांच करूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार यह विचार करेगी कि संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के विशेषज्ञ उन परियोजनाओं में पहुँच न रखें जिनमें वे सहायता दे रहे हैं। क्या सरकार जब तक उनके विरुद्ध जांच पूरी नहीं हुई तो कोई उनके विरुद्ध निरोधक कार्यवाही करेगी ?

श्री मु० क० चागला : मैंने "रैम्पर्ट" के लेख को पढ़ा है। उसमें यह नहीं कहा गया कि इस संस्था को सी० आई० ए० से राशि मिल रही है। उसमें अधिक से अधिक यह कहा गया है कि कुछ कार्यकर्ता यहां सी० आई० ए० के एजेंट थे। इसलिए इन एक दो कर्मचारियों के कारण जो कि सी० आइ० ए० के कभी कर्मचारी थे, के कारण सारी एजेंसी को कैसे काली सूची में रख सकते हैं ?

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में हड़ताल

\+

अल्प-सूचना	**श्री यशपाल सिंह :**	**डा० राम मनोहर लोहिया :**
प्रश्न संख्या 2	**श्री विश्वनाथ पांडेय :**	**श्री जार्ज फरनेंडीज :**
	श्री स० चं० सामन्त :	**श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :**
	श्री मधु लिमये :	

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के लगभग 2000 कर्मचारियों ने 16 मई, 1967 से हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार उनकी मांगों पर कब तक निर्णय कर लेगी ?

योजना पेट्रोल तथा रसायन और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) 16 मई, 1967 से लगभग 1600 कर्मचारियों ने हड़ताल की है ।

(ख) अग्रिम तरक्की, तदर्थ बोनस और खर्च के निर्वाह-सूचकांक का मंहगाई भत्ते से मिलान पर, कर्मचारियों की मांगों पर भिन्नता ही इसके कारण हैं ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के तत्वाधान में इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए बातचीत चल रही है । पहली दो मांगें स्वीकृत नहीं की गई हैं परन्तु यह विचार है कि मंहगाई भत्ते का प्रश्न सुलह बोर्ड को भेजा जाए । इन मांगों का फैसला करने में भारत सरकार का कोई संबंध नहीं कि है किन्तु हड़ताल को तत्काल समाप्त कराने के लिए अति इच्छुक है ।

Shri Yashpal Singh : To what extent the production has been affected by this strike ?

श्री रघुरमैया : हड़ताल की अवधि के दौरान उत्पादन पर काफी असर पड़ा है। अमोनिया के उत्पादन में 6 प्रतिशत की कमी हुई है, उरिया के उत्पादन में लगभग 26 प्रतिशत की और नाइट्रोफॉस्फेट के उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की ।

Shri Yaspal Singh : What was the reason for the refusal to talk with the Chief Minister ?

श्री रघुरमैया : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक समझौता हो गया है और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने काफी सहायता की है ।

Shri Vishwanath Pandey : May I know whether the Union has also been represented in the Board to which the matter relating to dearness and interim relief has been referred to under the Industrial Disputes Act ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : Yes, Sir

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि इन मजदूरों ने पहले दो बार हड़ताल की सूचना दे दी थी और यदि हाँ, तो पहले निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : पहले एक करार तय पाया था और संघ सहमत हो गया था कि हड़ताल करने की कोई बात नहीं है । उन्होंने 10 मांगें रखीं थी जिनमें से 7 का निबटारा कर दिया गया था और 3 बाकी रह गई थीं । परन्तु इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच के सभी झगड़े इस समय मजूरी बोर्ड के समक्ष भी हैं और प्रबन्धकगण मजूरी बोर्ड के विभिन्न अन्तरिम पंचाटों को क्रियान्वित करता रहा है और मजूरी बोर्ड में संघ और नियोजक दोनों के प्रतिनिधि हैं ।

Shri Madhu Limaye : Whether the Government have madeany efforts to strike a settlement earlier similar to the one which has been arrived at now ? To what extent the ferter production was affected and what amount of expenditure was incurred by Corporation or the Government to put an end to this strike ?

Shri Asoka Mehta : On the 22nd instant a settlement was reached between the Union and the management and it was hoped the factory would start functioning on the 23rd instant. But due to some reasons the union workers did not agree with the unions leaders and it took sometime and therefore, as has already been stated it is hoped that the work will commence today.

Shri Madhu Limaye : Why the strike was not prevented ?

Shri Asoka Mehta : I have dealt this point in the preceding question. If the hon. Member wants I can repeat it.....

Shri Madhu Limaye : Was any expenditure incurred on breaking the strike and to what extent there has been a fall in production ?

Shri Asoka Mehta : The point relaing to production has also been dealt in the answer. The hon. Member spoke of breaking the strike, I do not know what is meant by breaking the strike. To continue the production of fertiliser is the concern of the Fertiliser Corporation.

Shri George Fernandes : One thing I want to make clear. The statement of the hon. Minister that the strike was launched in respect of certain matters pending before the Wage Board is not correct. A settlement had been reached between the Fertilizer Corporation and the union and that settlement provided for the issue of dearness allowance would be resolved in a joint meeting within two months and that if it could not be resolved within two months, the mediation of the Labour Minister of Maharashtra Government would be sought for the purpose. The strike was resorted to only after five months has passed and not merely two months within which the issue should have been resolved. The hon. Minister has misled the House.

अध्यक्ष महोदय : यह सब पृष्ठभूमि है, मैं सहमत हूं । परन्तु प्रश्न कहाँ है ?

Shri George Fernandes : Now I come to the question. Fertilizer Corporation is a public sector industry and in my opinion there should not have been any strike there if the only demand of the union that the matter should be referred to the Tribunal for adjudication, had been acceded to. There was such provision in the agreement.....

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं ही प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं । फिर मन्त्री को उसका उत्तर क्यों देना चाहिये ।

Shri George Fernandes : But for the maltreatment meted out by the management the strike could have been a averted. The strike lasted for twelve days and I do not know in what manner the hon. Minister has calculated the expenditure. The hon. Minister should categorically the expenditure that has been incurred to put an end to the strike. During the last 12 days food costing Rs. 5,000 daily.....

Mr. Speaker : Order, order.

Shri George Fernandes : Is it not a fact that food costing Rs. 5, 000 daily was not being served to the Pressmen in the house of Dr. Mukerjee, the General Manager, from the four big hotels, viz. Gaylord, Volga, Paris and Khyber ? Was wine not served to the pressmen daily in the General Manager's house ? Was public money not squandered in this manner ?

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने सदन को गुमराह किया है । मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये । भारत का उर्वरक निगम एक बहु एकक निगम है । भारत के बहुत से भागों में इसके एकक हैं । अतः इस विशिष्ट निगम तथा समूचे तौर पर उर्वरक उद्योग की समस्याओं को एक राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि मामलों को

यूनिट वार नहीं निपटाया जा सकता । हम एक कारखाने में जो कुछ करते हैं वह हमें अन्य कारखानों में भी लागू करना पड़ता है । अतः इस प्रकार के निगमों में सामान्य नीति यह होती है कि मामले को राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को भेजा जाये । यह पहले हो चुका है । ऐसा पहले ही किया जा चुका है ।

निगम में हम, केन्द्रीय सरकार जो मंहगाई भत्ता देती है उसके अनुसार भत्ता देते रहे हैं । वह दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त मजूरी बोर्ड द्वारा कुछ अन्तरिम सहायता का सुझाव दिया गया था । वह भी क्रियान्वित किया जा चुका है । यदि अब भी संघ की एक माँग यह रह जाती है कि दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ दी जाँयें, तो मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है । कोई भी 10 वेतन वृद्धियाँ मांग सकता है, परन्तु क्या एक सरकारी क्षेत्र के कारखाने के इसको मानना संभव है ?

Shri George Fernandes : Why was it not referred for adjudication ?

श्री अशोक मेहता : जबकि पहले से ही एक मजूरी बोर्ड है तो क्या न्यायनिर्णयन को स्वीकार करना उचित होगा ? जब महाराष्ट्र की सरकार ने यह महसूस किया कि मामले को समझौते के लिये निदिष्ट किया जाये, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया । परन्तु इसमें .....(व्यवधान).....माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं । मुझ पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाने के बाद वह मेरी बात भी सुनना नहीं चाहते ।

Shri George Farnendes : Even now the hon. Minister is misleanding the House.

अध्यक्ष महोदय : सभा स्वयं इस बात का फैसला कर लेगी कि वह सभा को गुमराह कर रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं ।

श्री अशोक मेहता : उत्पादन के स्तर को बनाये रखने के लिये मैं अधिकारियों की प्रशंसा करना चाहता हूँ । मेरे साथी ने कहा है कि किस हद तक उत्पादन का स्तर बनाये रखा गया था । मुट्ठी भर अधिकारियों ने बड़े परिश्रम से और कड़े दबाव के अन्दर उत्पादन को बनाये रखा है जो कि महत्वपूर्ण है । यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में हड़ताल की गई जबकि हमें उर्वरक की सख्त जरूरत है । परन्तु इसके बावजूद अधिकारियों ने उत्पादन को बनाये रखा । मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि यह कितना महंगा पड़ता है । उन्होंने जो देश भक्ति दिखाई है उसके लिये मैं उसकी प्रशंसा करता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions.

भारत को शस्त्रों के विक्रय पर संयुक्त रूप से प्रतिबन्ध लगाना

***126. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी से भारत को शस्त्रों के विक्रय पर संयुक्त रूप से किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने की वांछनीयता के बारे में कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में इन देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार के पास सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण का प्रभाव

* **127. श्री अनन्तराव पाटिल :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से विज्ञापनों के प्रस्तावित प्रसारण का छोटे समाचार पत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में छोटे समाचार पत्रों को क्या सहायता देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी नहीं । सरकार ऐसा नहीं सोचती कि आकाशवाणी से व्यावसायिक प्रसारण करने से छोटे समाचार-पत्रों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा । तो भी, उनके हितों का बराबर ध्यान रखा जायेगा ।

Violation of Indian Air Space By Pakistan

***128. Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Swell
Shri D. C. Sharma :
Shri Meetha Lal :
Shri Ram Chandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Heerji Bhai :
Shri K. Pradhani :
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of violations of the Indian Air space committed by the Pakistani aeroplanes during the year 1966-67 and up-to-date ; and

(b) the action taken by Government to check such violations ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) According to information so far available to Government, there were 42 violations of Indian air space by Pakistani aircraft during the year 1966-67 and to- date.

(b) Protests about air space violations over areas, other than J. & K., were lodged with the Government of Pakistan. Complaints about air space violations in J. & K. area were lodged with the U. N. Observers. One Pakistani aircraft was shot down by I. A. F., aircraft in Punjab area on 2nd February, 1967.

परमाणु बम का निर्माण

*129. डा० करणी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री समर गूह :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निवारण के लिये परमाणु बम बनाना उचित समझती है, क्योंकि अब भारत चाहता है कि परमाणु शस्त्रों वाले देश उसको परमाणु हमले से सुरक्षा की गारंटी दें, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) परमाणु शक्ति का केवल शान्तिमय उद्देश्यों के लिए विकास करने की नीति का हमने दृढ़ता से अनुचरण किया है । इस नीति का हमारी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रश्न पर स्वभावतः निरन्तर विचार किया जाता है । जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं और जो निर्दलीय भी हैं उनकी, विशेषत : हमारे अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रश्न सदा सरकार के ध्यानाधीन रखा जाता है । भारत सरकार मुख्य परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों और कुछ निर्दलीय देशों से इस विषय पर विचार विमर्श करती रही है ।

बर्मा से स्वदेश लौटे हुए भारतीयों को मुआवजे का भुगतान

* 130. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एम० रामपुरे :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री एन० के० सांघी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री मद्दो सुदर्शनम् :
श्री सेहीयान :
श्री के० अम्बाजगन :

वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार से स्वदेश लौटे हुए भारतीयों का मुआवजा चावल के रूप में मांगने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ग) इससे खाद्य स्थिति में किस हद तक सुधार होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बर्मा सरकार द्वारा भारतीय देश प्रत्यावर्तियों को संपत्ति का मुआवजा देने के सवाल पर दोनों सरकारों के बीच अब भी बातचीत चल रही है । बहरहाल, मुआवजे के रूप में उनसे चावल मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बर्मा जितना भी चावल बचा सकता है, वह सब हम पहले ही खरीद रहे हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का लगाया जाना

*131. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर, जोधपुर, कोटद्वार और मथुरा में 100 किलोवाट शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि सीमा क्षेत्रों तथा उत्तर भारत में सामरिक महत्व के स्थानों पर प्रचार के उद्देश्य से उक्त ट्रांसमीटरों के लिए विशेष रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 100 किलोवाट शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर जिसे गोरखपुर में लगाया जाना था अब त्रिचूर भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तीन स्थानों अर्थात गोरखपुर, जोधपुर, और कुमाऊं/गढ़वा क्षेत्र के लिए नजीबाबाद में ट्रांसमीटर लगाने के स्थान चुने जा चुके हैं । इन परियोजनाओं के लिए साज़ सामान के लिए पहले ही आर्डर दिया जा चुका है और उनके शीघ्र ही मिलने की आशा है । मथुरा में उच्च शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अलबत्ता, मथुरा में, एक अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर वाला एक नया रेडियो, स्टेशन 29 जनवरी, 1967 को चालू हो चुका है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

*132. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री एस० आर० दमानी :
डा० रानेन सेन :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री के० प्रधानी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष में राज्यवार अब तक कुल कितना सोना तथा नगदी आई है :

(ख) देश की रक्षा के लिये अब तक कुल कितनी धन राशि खर्च की गई है : और

(ग) शेष धन राशि किस प्रकार व्यय की जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :(क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 420/67**

(ख) अब तक 27. 27 करोड़ रुपये रक्षा-उपकरण के क्रय पर व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) शेष धन रक्षा प्रयत्नों की उन्नति करने के लिए एवं फौजी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कल्याण के हेतु व्यय किया जायगा।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं और बौद्धों का प्रव्रजन

*133. **श्री डी० एन० पटौदिया :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वाई० एस० कुशवाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं और बौद्धों ने भारत में हाल में धीरे-धीरे प्रव्रजन किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में कितने व्यक्तियों ने प्रव्रजन किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस बारे में बातचीत की है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सुलभ सूचना के अनुसार, नवम्बर 1966 से अप्रैल 1967 तक की अवधि में अल्पसंख्यक जातियों के कुल मिलाकर 7,171 व्यक्ति भारत आए।

(ग) भारत सरकार ने पूर्व पाकिस्तान की सरकार से वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की मुसीबतों के बारे में कई बार शिकायतें की हैं और उन्हें नेहरू-लियाकत समझौते के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई है जिसमें उनसे अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पूरी आजादी और समान अधिकार देने को कहा गया है। दुर्भाग्य से, पाकिस्तान सरकार ने इसके विरूद्ध अपनी कथनी के बावजूद वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने के लिए बहुत ही कम काम किया है।

छोटे समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा

*134. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज का कोटा कम होने के कारण छोटे समाचार-पत्रों को अभी तक कठिनाइयां हैं; और

(ख) यदि हां, तो छोटे समाचार पत्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1967–68 में अखबारी कागज़ एलाट करने सम्बन्धी नीति में छोटे समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज़ के कोटे में प्रचुर वृद्धि की उचित व्यवस्था की गई है।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*135. **श्री मनीभाई जे० पटेल :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री एम० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री रणजीत सिंह।
श्री जे० बी० सिंह :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री दी चं० शर्मा :
श्री लोलाधर कटको :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री रा० बरुआ
श्री सी० सी० देसाई :
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत विरोधी प्रचार तेज कर दिया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में अमरीकी घोषणा से पाकिस्तान को यह आन्दोलन तेज़ करने में बल मिला है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को कथित स्वतन्त्रता को एक सबका मिला जुला उद्देश्य बनाने के लिए मुस्लिम देशों का एक सम्मेलन बुलाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी हां। ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर होने के कुछ समय बाद से ही पाकिस्तान ने भारत-विरोधी प्रचार शुरू कर दिया और वह बेरोक-टोक चलता रहा है। अब वह बहुत ज़ोरों पर है।

अमरीका के इस निर्णय से भारत-विरोधी अभियान और बढ़ गया मालूम होता है कि पाकिस्तान द्वारा पहले लिए गए घातक हथियारों के फालतू पुर्जे नगद खरीद कर लिए जायेंगे और अनुदान के आधार पर सैन्य सामग्री देना बंद कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) : तमाम मुस्लिम देशों का सम्मेलन बुलाने और कथित कश्मीर को आज़ादी का समान लक्ष्य बनाने की दृष्टि से उसका उपयोग करने को जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उसको भारत सरकार को जानकारी है। सच तो यह है कि अप्रैल 1967 में पाकिस्तान ने मोत्तमर अल-आलम अल-इस्लामी (विश्व मुस्लिम कांग्रेस) को मीटिंग करने

का निमंत्रण दिया था ; यह एक गैर-सरकरी संस्था है जहां कुछ प्रतिनिधियों ने कठोर भारत विरोधी वक्तव्य दिए थे ।

पाकिस्तानी विधि मंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय उलेमा सम्मेलन की संगठन समिति की बैठक में श्री जाफर ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने सर्वोच्च उलमाओं और मुस्लिम संसार के धार्मिक नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय उलेमा सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया है जिसका उद्देश्य होगा, मुस्लिम राष्ट्रों के सम्मुख महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करना। यह बैठक अगले अक्टूबर में रावलपिंडी में होगी ।

सरकार हमेशा से ही पाकिस्तान द्वारा की जानेवाली इस तरह की कोशिशों के प्रति सचेत रही है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का उपयोग किया जाय और इस तरह की कोशिशों को खत्म करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं । बहुत से प्रगतिशील इस्लामी देश भी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का दूरुपयोग करने के सख्त खिलाफ है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति बनाये रखने के लिये कार्यवाही

* 136. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ज्ञापन में यह घोषणा की है कि वह शान्ति बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गयी ऐसी कार्यवाही के लिये धन देने में सहायता नहीं करेगा जिसका वह अनुमोदन नहीं करता और वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में किये गये निर्णयों को मानने के लिये बाध्य नहीं होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस घोषणा के बारे में अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सोवियत संघ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उपायों से संबद्ध सारे सवालों का फैसला करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत सिर्फ सुरक्षा परिषद को है ।

(ख) और (ग) अन्य सदस्य राज्यों का मत कुछ भिन्न है, और महासभा के वर्तमान विशेष अधिवेशन में इन मतों पर विचार किया जा रहा है ।

डा० कोनराड आडेनावर की अन्त्येष्टि

* 137. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी के डा० कोनराड आडेनावर की अन्त्येष्टि में शामिल होने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि का नाम क्या है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री अथवा मंत्रि मंडल के किसी अन्य सदस्य ने इस अवसर पर सरकार का प्रतिनिधित्व किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पश्चिम जर्मनी में डा० कोनराड आडेनावर की अन्त्येष्टि में संसद सदस्य, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

(ख) और (ग) : पहले से ही व्यस्त होने के कारण, न तो प्रधान मंत्री और न विदेश मंत्री ही इस अवसर पर जर्मनी जा सके। सब परिस्थितियों को देखते हुए और श्रीमती पंडित के राजनयिक अनुभव की विशिष्ट पृष्ठभूमि को देखते हुए, उन्हें डा० आडेनावर की अन्त्येष्टि में भारत का प्रतिनिधित्व करने के सर्वथा उपयुक्त समझा गया।

विदेश मंत्री तथा विदेश सचिव द्वारा विदेशों का दौरा

***138. श्री नाथ पाई :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री एन० के० सांघी :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री शारदा नन्द :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कू :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री काशीनाथ पांडे
श्री डी० एन० देव :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री एस० के० तापड़िया :
श्री वाई० जी० गौड :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय और विदेश सचिव ने अप्रैल, 1967 में कुछ विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और दौरा करने का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) इसकी उपलब्धियां क्या हैं ?

गैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) मैंने निम्नलिखित देशों की यात्रा की :-

कुवैत
ईरान
स्विट्जरलैंड (जेनेवा, बर्न)

इन यात्राओं के बारे में 22 मई 1967 को सदन में एक वक्तव्य दिया गया था । विदेश सचिव ने निम्नलिखित देशों की यात्रा की :-

यूगोस्लाविया
संयुक्त अरब गणराज्य
स्विट्जरलैंड (जेनेवा)
इटली

इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य था-आपसी हित के मामलों पर, खासकर परमाणु अस्त्रों के प्रसार-विस्तार पर, अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करना ;

(ग) इन यात्राओं के परिणाम इस दृष्टि से संतोषजनक थे कि परमाणु अस्त्रों के प्रचार विस्तार पर भारत के विचारों की पूरी तरह सराहना की गई ।

राष्ट्रीय छात्र सेना का अनिवार्य प्रशिक्षण

*139. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री वी० एस० शर्मा :
श्री पी० के० वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री पी० सी० अदिचन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विसूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय छात्र सेना की अनिवार्य प्रशिक्षण योजना को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विद्यार्थियों में राष्ट्रीय छात्र सेना के लक्ष्यों में निहित आदर्शों की भावना पैदा करने के लिये कोई वैकल्पिक योजना भी है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) : 1962 में चीनी आक्रमण के बाद जनता की आम मांग पर 1963 में कालेज के लड़कों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कौर का प्रशिक्षिण अनिवार्य केवल इसलिए ही नहीं कर दिया गया था कि इससे

उनके चरित्र का विकास होगा और उनमें मित्रता, सेवा के आदर्श और नेतृत्व की क्षमता आएगी अपितु इसलिए भी कि देश रक्षा के प्रति उनकी अभिरूचि बढ़ेगी और राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को जल्दी ही बढ़ाने के लिए पहले ही से एक शक्तिशाली जनशक्ति बना कर रख सकेंगे। अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक अधिसूचना के बाद सभी विश्वविद्यालयों ने सभी कालेज छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाते हुए अध्यादेश जारी किए। तब से निम्नलिखित बातों को देखते हुए इस मामले का परीक्षण किया गया :—

(1) प्रति वर्ष कालेजों में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के परिणामस्वरूप कालेज छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन की बढ़ती हुई संख्या शक्ति, जो रक्षा आवश्यकताओं से असम्बन्धित है।

(2) प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण अमला और उपस्कार की वर्तमान लगातार कमी।

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर में अनिवार्य रूप से भाग लेने में विद्यार्थियों में अभिरूचि की कमी और हिचकिचाहट।

(4) विश्वविद्यालयों में और विशेष कर शिक्षाविदों में बढ़ती हुई यह भावना कि राष्ट्रीय कैडेट कौर प्रशिक्षण को ऐच्छिक बनाया जाय, और

(5) राष्ट्रीय सेवा कोर (नेशनल सर्विस कोर) बनाने के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग और कुठारी समिति की सिफारिश।

अब राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को ऐच्छिक बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

Newsprint Policy

*140. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri Surendranath Dwivedy :**
Shri Hem Barua : **Shri Virendra Kumar Shah :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new policy has been formulated in respect of newsprint ;

(d) if so, the main features thereof ; and

(c) the impact thereof on the newspaper industry ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir,

(b) A statement is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. LT 421/67)**

(c) The newspaper industry have generally welcomed the current year's newsprint allocation policy.

भारत को अमरीकी हथियारों का सम्भरण

*** 141. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 के चीनी आक्रमण के बाद अमरीका ने आपातकालीन

सहायता के अन्तर्गत जो अमरीकी सैनिक सामान देने का वचन दिया था, उसमें से केवल आधा सामान ही भारत को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीकी सरकार द्वारा वचन पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (**श्री स्वर्ण सिंह**) : (क) से (ग) नवम्बर 1962 में अमरीका सरकार चीनी आक्रमण का मुकाबिला करने के लिए 600 लाख टर्लिग की कीमत के भण्डार और उपस्कर देने को सहमत हुई थी । उसके बाद दो और कार्यक्रम प्रत्येक 500 लाख स्टर्लिग की कीमत के गये । इस प्रकार कुल 1600 लाख स्टर्लिग की कीमत के सैनिक सामान देने की व्यवस्था की गई । इन कार्यक्रमों से सितम्बर 1965 तक कुल लगभग 760 लाख स्टर्लिग की कीमत का सैनिक सामान प्राप्त हुआ ।

सितम्बर 1965 में भारत-पाक संघर्ष के दौरान अमरीका सरकार ने सहायता कार्यक्रम बन्द कर दिया था और वह अभी तक पुनः चालू नहीं हुआ है । केवल अमरीका में पारस्परिक रूप से स्वीकृत कोर्सों में सैनिक अफसरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी हाल ही में फिर से चालू किया गया है ।

खान अब्दुल गफ्फार खां को निमंत्रण

* **142. श्री स्वैल :**
श्री आर० के० बिरला :
डा० करणी सिंह :
श्री कीकर सिंह :
श्री कोलाई बरुआ :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हेम राज :
श्री मंगलाथुवाडम :
श्री पी० विश्व प्रभरन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत आने के लिए पुनः निमंत्रण दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निमंत्रण के बाद बादशाह खां से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) वह भारत कब आ रहे हैं; और

(घ) उनके पख्तून आन्दोलन के लिए उन्हें क्या सहायता दी जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह**) : (क) से (ग) जनवरी

1965 में खान अब्दुल गफ्फार खां को जब उनकी मर्जी हो तब भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। चूंकि बादशाह खान ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि वे किसी उपयुक्त समय पर भारत की यात्रा करेंगे इसलिए उन्हें नए सिरे से और निमंत्रण नहीं दिया गया है।

(घ) इस बारे में भारत सरकार के विचार अच्छी तरह जाने-माने हैं और कई बार सदन में व्यक्त किए जा चुके हैं। सरकार को पख्तूनों की वैध आकांक्षाओं से पूरी सहानुभूति है और वह संवैधानिक रीति से यथासम्भव उनका समर्थन करेगी।

राजदूतों के पदों पर नियुक्तियां

* 143. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजदूतों के पदों पर पराजित मंत्रियों की नियुक्तियां करने के बारे में कोई नीति निर्धारित की है ;

(ख) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी को इंगलिस्तान में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है;

(ग) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इंगलिस्तान में उच्च आयुक्त के रूप में कार्य करने की अपनी अवधि में मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री के बराबर की पदस्थिति की मांग की है; और

(घ) क्या यह नियुक्ति सरकार द्वारा-बर्ड एण्ड कम्पनी के जुर्माने में कमी किये जाने के मामले में की जा रही जांच के आधार पर भूतपूर्व वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निर्धारित की जाने से पहले की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चूंकि राजदूत के पद पर नियुक्ति राजनयिक कार्यभार की उपयुक्तता के आधार पर की जाती है, इसलिए, ऐसे पदों पर पराजित मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में कोई विशेष नीति नहीं है।

(ख) इस तरह के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन तभी खत्म कर दिया गया।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

एच० एफ०-24 जैट विमान

* 144. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री एस० एस० कोठारी :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री वृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
डा० रानेन सेन :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित एच० एफ०–24 विमान एयरफ्रेम में लगाये गये मिश्र में निर्मित सुपरसानिक जैट विमान के इन्जन हाल में हुई परीक्षण उड़ानों के समय पहली जांच में ठीक पाये गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के अन्तर्गत अब विधिवत निर्माण आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग की क्या संभावनायें हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) एच० एफ० –24 विमान ने ई–300 इन्जन के साथ 29 मार्च 1967 को पहली परीक्षण उड़ान की, और आगे उस पर विकास उड़ानें की जा रही हैं। उड़ान परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद ही सुपरसानिक विमान के निर्माण में सहयोग का प्रश्न उठेगा।

चीन द्वारा कोलम्बो प्रस्तावों का उल्लंघन

*** 145. श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों के उपबन्धों का न केवल लद्दाख बल्कि नेफा में भी खुले आम उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब भी कोलम्बो प्रस्तावों से बंधी हुई है जबकि चीन के दुराग्रह के कारण अब उनका लेशमात्र भी महत्व नहीं रहा है; और

(ग) कोलम्बो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार का रवैया अब भी यही है कि वह कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर चीन से बातचीत करने को तैयार है।

(ग) कोलम्बो प्रस्तावों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने के बावजूद, चीनियों ने बाकायदा उनका खण्डन नहीं किया है। जहां तक हमारा सवाल है, हमने शुरू में जो स्वीकार किया था, उसे अब भी स्वीकार करते हैं। छह अफ्रो–एशियाई देशों ने भी, जिन्होंने कि इन प्रस्तावों को तैयार किया था, सामूहिक रूप से अथवा अलग-अलग ही, इनमें संशोधन करने या इन्हें वापस लेने के लिए कोई कार्यवाई की है। इसलिए, ये प्रस्ताव अब भी वैध बने हैं।

पाकिस्तान द्वारा आण्विक बम का विस्फोट

*** 146. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री स्वैल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के आण्विक क्लब का सक्रिय सदस्य होने के अतिरिक्त पाकिस्तान भी इस क्लब में प्रवेश करने जा रहा है और 1968 तक अपने पहले आण्विक बम का परीक्षण करने का इरादा रखता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया है कि चीन-पाक के इस संयुक्त उद्यम से भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को इस मामले के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है । 2 अप्रैल 1967 के 'पाकिस्तान टाइम्स' की एक खबर में कहा गया था कि पाकिस्तान में एक "सुपर बम" बना लिया गया है, लेकिन, स्पष्टतः यह कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं थी ।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार को इस बात का पक्का भरोसा है कि वह निश्चित रूप से राष्ट्र की सुरक्षा कर लेगी लेकिन, यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि इस उद्देश्य से क्या-क्या उपाय किए गये हैं ।

Negotiations with Burmese Government Question

*147. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :
Shri R. S. Vidyarathi
Shri D. N. Patodia :
Shri S. Supakar :
Shri C. C. Desai :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 368 on the 3rd April, 1967 and state :

(a) whether negotiations regarding the release of assets of the Indians confiscated by the Burmese Government have since been completed ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) The matter is still under discussion with the Government of Burma.

पाकिस्तान को टर्की का समर्थन

* **148. श्री आत्मदास** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि टर्की के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का टर्की के साथ हमारे सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ; और

(ग) क्या इस विषय में टर्की की सरकार के साथ हमारे राजदूत के माध्यम से बातचीत की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1967 को राष्ट्रपति अय्यूब खां द्वारा आयोजित एक भोज में तुर्की के प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उनका देश "पाकिस्तान के वैध उद्देश्यों" में उसका समर्थन करता है। लेकिन, उनको यात्रा के अन्त में प्रकाशित सम्मिलित विज्ञप्ति में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस विज्ञप्ति में दोनों नेताओं ने "जम्मू और काश्मीर से संबद्ध झगड़े को, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अन्तर्राष्ट्रीय वायदों के सम्मान के आधार पर आत्म-निर्णय के सिद्धांत के अनुरूप जल्दी निबटाने का अनुग्रह किया है"। उन्होंने "इस क्षेत्र में बढ़ते हुए सैनिक असंतुलन से बचने की आवश्यकता पर भी बल दिया।"

(ख) तुर्की के प्रधान मंत्री ने भोज के समय के अपने भाषण में जिस समर्थन का ज़िक्र किया था उसका और सैनिक असंतुलन का अर्थ यह निकलता है कि उनका देश भारत के खिलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को हथियार और उपकरण देगा तो तुर्की के साथ हमारे संबन्धों पर इसका बुरा असर निश्चय ही पड़ेगा।

(ग) भारत सरकार इस बारे में तुर्की की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक सूत्रों के ज़रिये बराबर संपर्क बनाए हुये है।

वियतनाम में सैनिक कार्यवाही

*** 149. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीकी सरकार द्वारा वियतनाम में सैनिक कार्यवाही को हाल ही में बढ़ावा देने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्होंने वियतनाम में अमरीकी युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिये गये साक्ष्य के समाचार पढ़े हैं; और

(ग) एशिया के उस युद्ध संत्रस्त क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए भारत किस प्रकार अपना प्रभाव डालना चाहता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) इधर हाल ही में वियतनाम में सैनिक गतिविधियों की गति तेज हो जाने के बारे में भारत सरकार को खबरें मिली हैं। सरकार ने स्टाकहोम में हुए गैर-सरकारी ट्रिबुनल के बारे में भी अखबारों में खबरें देखी हैं।

(ग) भारत सरकार ऊथांट से, और वियतनाम को स्थिति से जिनका सीधा सम्बन्ध है, उनसे निकट संपर्क बनाये हुए है और वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिए सभी सम्भव कदम उठा रही है।

Violations of Indian Air Space

***150. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Heerji Bhai :
Shri K. Pradhani :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of Defence be pleased to state ;

(a) whether there have been violations of Indian air space by aeroplanes of some foreign countries during the last three months ;

(b) if so, the areas over which such violations have taken place ; and

(c) whether Government have sent some protest notes to the countries concerned ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The violations over areas in Assam, Tripura and West Bengal.

(c) Yes, Sir.

बाल फ़िल्म सोसाइटी

701. श्री बाबूराव पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल फ़िल्म सोसायटी द्वारा 1955 से लेकर अब तक कितनी फ़िल्में तैयार की गई हैं;

(ख) प्रत्येक फ़िल्म पर कितनी लागत आई है और इन सब वर्षों में प्रत्येक फ़िल्म से कितनी आमदनी हुई है;

(ग) विदेशों में दिखाने के लिए कितनी तथा किन-किन फ़िल्मों का निर्यात विदेशों में किया गया और उनसे कितनी आमदनी हुई;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) सोसायटी के स्थापना-काल से लेकर अब तक कितनी फ़िल्में भारत में दिखाई गई और कितने बच्चों ने ये फ़िल्में देखी;

(च) वर्ष 1967-68 में कितनी और कौनसी फ़िल्में तैयार करने का विचार है और प्रत्येक पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(छ) क्या देश में तथा विदेशों में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फ़िल्मों की वाणिज्यिक स्तर पर मांग है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 55

(ख) एक विवरण, जिसमें सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) केवल 'जलदीप' नामक फिल्म से, जो विदेशों में निर्यात की गई थी; 1,800 रुपये की आमदनी हुई ।

(घ) मांग की कमी :

(ङ) निर्माण की गई 55 फ़िल्मों में से 50 फ़िल्में, 1962 से सोसायटी द्वारा आयोजित फिल्म-शो के द्वारा 43,70,395 बच्चों और वयस्कों को दिखाई गई । 1962 से पहले की दर्शकों की संख्या प्राप्त नहीं है । ऊपर दी गई संख्या में उन दर्शकों की संख्या भी शामिल नहीं है, जिन्होंने सोसायटी द्वारा कुछ राज्यों, केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों और नगर निगमों को लीज पर दिये गये प्रिन्टों के आधार पर आयोजित फिल्म-शो देखे ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० ५२२/६७]

(च) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 422/67] ।

(छ) व्यापारिक स्तर पर स्कूलों में मांग नहीं है, परन्तु ये फ़िल्में भारत में प्रति शो के लिए एक निश्चित किराये पर अव्यापारिक आधार पर दिखाई जाती हैं ।

फिल्मों का आयात

702. श्री बाबू राव पटेल :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में कितनी विदेशी फ़िल्में-वृत्त चित्र, शिक्षाप्रद कार्टून और दूसरी किस्मों की फ़िल्मों का भारत में आयात किया गया;

(ख) जिन देशों से इनका आयात किया गया उनके नाम क्या हैं तथा उनसे आयात की गई फिल्मों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक आयातक ने भारत में इकट्ठे हुए धन में से कितना धन विदेशों को भेजा;

(घ) प्रत्येक आयातक ने कितना धन भारत में रखा;

(ङ) भारत में आयात की गई फ़िल्मों से प्राप्त तथा भारत में रखे गए धन का उपयोग आयातकों तथा वितरकों ने फ़िल्मों का आयात करने में किस प्रकार किया;

(च) यदि हां, तो उसके नियम तथा शर्तें क्या हैं;

(छ) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में विभिन्न विदेशी फ़िल्म वितरकों ने कुल कितना धन प्रति वर्ष विदेशों में भेजा; और

(ज) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में विदेशों में भारतीय फिल्मों ने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ज) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

भारत के समाचार पत्र

703. श्री बाबूराव पटेल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन समाचारपत्रों तथा प्रकाशकों को गत पांच वर्षों में अखबारी कागज का कितना तथा कितने-कितने मूल्य का कोटा दिया गया;

(ख) यह कोटा किस आधार पर दिया जाता है तथा यह देखने के लिये सरकार ने

क्या कार्यवाही की है कि अखबारी कागज का प्रयोग उसी काम के लिये किया जाता है, जिसके लिए यह दिया जाता है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि अखबारी कागज का कोटा कर-अदायगी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिये जाता है, जब कि व्यापार की अन्य वस्तुओं के आयात पर यह शर्त नहीं लगाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा हर साल आवेदन दिया जाने पर लगभग 2,500 समाचारपत्रों को अखबारी कागज दिया जाता है। अपेक्षिक जानकारी को इकट्ठा करने में जो समय और परिश्रम लगेगा वह शायद ही सम्भावित परिणामों के अनुरूप हो।

(ख) समाचार-पत्र का अखबारी कागज़ का कोटा उसकी प्रचार-संख्या, आकार, पृष्ठ-संख्या, आवधिकता और प्रकाशन में नियमितता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह कोटा हर साल अप्रैल मास में घोषित अखबारी कागज़ के बटवारे की नीति के अनुसार बदलता रहता है।

अखबारी कागज का कोटा देते समय, प्रचार-संख्या, आवधिकता, आकार, प्रकाशन में नियमितता आदि, जिनके आधार पर अखबारी कागज अलाट होता है; ताकि प्रार्थियों को अखबारी कागज का अधिक कोटा न मिल सके। देश के विभिन्न समाचार-पत्र अपनी प्रचार-संख्या के सम्बन्ध में जो दावे पेश करते हैं, भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार उनकी जांच-पड़ताल भी करवाते हैं। अखबारी कागज के कोटे के अनुचित प्रयोग के सन्दिग्ध मामलों को जांच करने वाले उचित अधिकारियों के पास आवश्यक कार्यवाई के लिये भेज दिया जाता है।

(ग) अखबारी कागज के कोटे की मात्रा सरकार की समय-समय पर घोषित नीति के अनुसार निश्चित की जाती है। यह कर-अदायगी प्रमाण पत्र पेश करने पर निर्भर नहीं होती। मान्य आय-कर जांच-पत्र/रजिस्ट्रेशन/छूट संख्या का पेश करना आयात लाइसेंन्स को देने से सम्बन्धित शर्तों में से एक जरूरी शर्त है। यह शर्त-सभी आयात के मामलों पर लागू होती है। इसलिए जब तक किसी अखबार का अखबारी कागज का कोटा 40 मीटर टन से कम न हो, अखबारी कागज के आयात के प्रार्थना-पत्रों के साथ भी मान्य आय-कर जांच-पत्र/रजिस्ट्रेशन/छूट संख्या देना जरूरी है।

ट्रान्समिशन रिसीवर

704. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इनके मंत्रालय ने हाल ही में यहीं के बने हुए ट्रांसमिशन रिसीवर खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) देशी साधनों से ही निर्मित ट्रांसमीटर और रिसीवर भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड कम्पनियों से खरीदे जा रहे हैं। इनकी खरीद के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण देना लोकहित में उचित नहीं है।

विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

705. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम और उनकी संख्या क्या है जिनके साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है; और

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों में कुल कितने भारतीय बसे हुए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 20, जिनके नाम है : मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नाइजर, चाड, ग्वाटेमाला, इक्वेडोर, कोस्टा रिका, हायटी, होंडुरास, डोमिनिकन गणराज्य, आइसलैंड, इसराईल, निकारागुआ, अल-साल्वेडोर, दक्षिण अफ्रीका, फारमोसा, पुर्तगाल, रोडेशिया, पूर्व जर्मनी, वियतनाम (उत्तर और दक्षिण) और कोरिया (उत्तर और दक्षिण) ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका – 18,500* (अनुमानतः)
यूनाइटेड किंगडम –1,70,000 (अनुमानतः)

* (इस संख्या में अमरीका में 1820 से रजिस्टर किए गए सभी भारतीय आप्रावासी सम्मिलित है)

राष्ट्रीय छात्र सेना दल

706. **श्री श्रीकान्तन नायर:** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने राष्ट्रीय छात्र-सेना दल पर अब तक कितना धन व्यय किया है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : राष्ट्रीय कैडेट कोर पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें व्यय करती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यय अलग से पूर्व निर्धारित नहीं होता। इसलिए इस पर ठीक कितना व्यय होता है यह बताना सम्भव नहीं है। फिर भी ऐसा अनुमान है कि 1964–65, 1965–66 और 1966–67 के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इस पर संयुक्त रूप से क्रमशः लगभग 20.9 करोड़ रुपये, 20.77 करोड़ रुपये और 25.11 करोड़ रुपये व्यय किए ।

आकाशवाणी में मकैनिक

707. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में काम करने वाले ऐसे मकैनिकों की कुल संख्या कितनी है जो न तो मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास हैं और न अर्हता प्राप्त मकैनिक हैं;

(ख) क्या सरकार भविष्य में मकैनिकों के पद को भरने के लिए तकनीकी और शैक्षणिक अर्हता की सीमा निर्धारित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो निर्णय कब तक कर लिया जायेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) आकाशवाणी में मैकेनिक के पद के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित नहीं है। मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) इस प्रश्न पर कि क्या आकाशवाणी में मैकेनिक पद पर भर्ती के लिए निर्धारित की हुई अर्हताओं में संशोधन की आवश्यकता है, विचार किया जा रहा है।

आकाशवाणी में मैकेनिकों की पदोन्नति

708. श्री अब्दुल गनी डार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के मैकेनिक ट्रान्समिटरों पर इन्जीनियरिंग असिस्टेंटों का काम स्वतन्त्र रूप से कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इन्जीनियरिंग असिस्टेंटों के पद पर पदोन्नत कर दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को ऐसा अभ्यावेदन मिला था कि उन मैकेनिकों को इन्जीनियरिंग असिस्टेंटों के पद पर पदोन्नत करने के लिए निर्धारित वर्तमान कोटे की प्रतिशतता बढ़ाई जाये; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी के मैकेनिकों का काम इन्जीनियरिंग स्टाफ़ की यन्त्रों की मरम्मत व देखभाल करने में, उन्हें लगाने में और परीक्षण कार्य में सहायता करना है। वे ट्रान्समीटरों/कन्ट्रोल-रूमों/रिसीविंग केन्द्रों पर शिफ्ट ड्यूटी भी देते हैं तथा जो इन्जीनियर ड्यूटी पर होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इन्जीनियरिंग सहायकों के काम में नीचे लिखी बातें आती हैं–

1. स्टूडियो, रिसीविंग और ट्रांसमीटिंग केन्द्रों पर ट्रांसमीशन ड्यूटी।
2. रिकार्ड और डब करने का काम।
3. स्टूडियो के बाहर के प्रसारण से सम्बन्धित काम।
4. उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के शार्ट वेव एरियल से सम्बन्धित काम।
5. यंत्रों की देखभाल और उनको लगाने के काम में सीनियर स्टाफ की सहायता करना।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। आकाशवाणी के मैकेनिकों के दो ग्रेड हैं–एक 130-5-175-दक्षतारोध 6-205 रुपये के वेतनमान में और दूसरा, जिसको सीनियर मैकेनिक कहा जाता है, 150-5-

175-6-205-दक्षतारोध-7-240 रुपये के वेतन मान में। सीनियर मैकेनिक के पदों पर पूर्ण रूप से मैकेनिक के पदों से पदोन्नति की जाती है। इस समय 210-10-290-15-320-15-425-दक्षतारोध-15-470 रुपये के वेतनमान वाले इन्जीनियरिंग सहायक के ग्रेड के पदों में से 5 प्रतिशत पद सीनियर मैकेनिक के पदों में से पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। सीनियर मैकेनिक के पदों से पदोन्नति के वर्तमान 5 प्रतिशत कोटे को बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) 5 प्रतिशत के कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी के तीसरी श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

709. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों के सेवा की शर्तों पर विचार करने के लिये आकाशवाणी के महानिदेशक ने एक आंतरिक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी;

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी;

(घ) क्या इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होने में विलम्ब के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) जी, हां।

(ख) समिति अक्टूबर, 1965 में नियुक्ति की गई थी।

(ग) कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है।

(घ) जी, हां; रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, यह मिला था।

(ङ) अभ्यावेदन देने वालों को यह बता दिया गया था कि समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

आकाशवाणी में मैकेनिक

710. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में काम करने वाले ऐसे सीनियर और जूनियर मैकेनिकों की संख्या कितनी है जो अपने वेतनक्रम में अधिकतम वेतन ले रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से अर्हताप्राप्त तथा अनुभवी मैकेनिक इसलिए आकाशवाणी की नौकरी छोड़कर चले गये हैं क्योंकि वहां पदोन्नति के अवसर कम हैं;

(ग) क्या उनके वेतनक्रम की अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है;और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) से (ङ) इस समग्र प्रश्न पर कि क्या आकाशवाणी में काम करने वाले तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों, जिनमें मैकेनिक और सीनियर मैकेनिक भी शामिल हैं, के वेतन-मानों में संशोधन की आवश्यकता है, विचार हो रहा है । इस मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने में कुछ समय लगने की संभावना है ।

आकाशवाणी में कार्यभारित कर्मचारी

711. श्री अब्दुल गनी दार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में ऐसे कितने कार्यभारित कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से सेवा कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है;

(ग) कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ;

(घ) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के .के. शाह) : (क) 20

(ख) कोई नहीं ।

(ग) 20

(घ) और (ङ) उन्हें नियमित करने के लिए कुछ नियमित पदों को बनाने के लिए कार्यवाई की जा रही है ।

राजस्थान में पाकिस्तानी अपराधियों की गतिविधियां

712. श्री पी० एम० सईद :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि 16 अप्रैल, 1967 को ऊंटों पर चार सहस्त्र पाकिस्तानी अपराधी सीमावर्ती गुलुवाली गांव में घुस आये और उन्होंने गांव वालों को लूटा;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानियों की ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) और (ख) जी हां। 16 अप्रैल 1967 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन, 8/9 अप्रैल की रात को गुलुवाली, थाना पुगल, ज़िला बीकानेर में ऐसी ही एक घटना हुई थी। घटना का ब्यौरा इस प्रकार है :

दो ऊंटों पर 4 पाकिस्तानी अपराधी भारतीय प्रदेश में घुस आए और उन्होंने 8/9 अप्रैल 1967 की रात को गुलुवाली गांव में 2450 रुपये की संपत्ति चुरा ली। ये अपराधी चोरी की संपत्ति लेकर पाकिस्तानी प्रदेश में वापस चले गये।

पाक सीमांत अधिकारियों से इस मामले की जांच-पड़ताल करने को कहा गया और इसके बाद 15 अप्रैल 1967 को एक फ्लैग मीटिंग हुई जब पाकिस्तान ने चोरी की गई संपत्ति लौटा दी और वह उसके असली मालिक को दे दी गई।

(ग) अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए सीमा पर काश्त बढ़ा दी गई है।

(घ) ग्राउन्ड रूल्स के अनुसार, सीमा सुरक्षा सेना इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट अपने समकक्ष सीमा चौकी कमांडर को देती है और वह इसको पावती स्वीकार करता है तथा अपने देश के नजदीकी थाने को इसकी सूचना दे देता है जो कि संपत्ति को निकालने की पूरी कोशिश करता है। संपत्ति मिल जाने पर, दूसरे पक्ष के सीमांत अधिकारियों को सौंप दी जाती है। इस विशेष मामले में चोरी की हुई संपत्ति 15 अप्रैल 1967 को लौटा दी गई और इस तरह कोई और विरोध-पत्र पाकिस्तान सरकार के पास नहीं भेजा गया।

त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा घुसपैठ

713. **श्री विश्वनाथ राय**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा
श्री एन० के० सांघी
श्री वाई० ए० प्रसाद
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल, 1967 को पूर्वी पाकिस्तान सशस्त्र सेना का एक दल त्रिपुरा में भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) जी हां। 10 अप्रैल 1967 को दोपहर के साढ़े बारह बजे कुछ पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारियों की मदद से भारतीय प्रदेश में सदर सब-डिवीज़न के थाना कोतवाली के भागलपुर

गांव में घुस आए । भारतीय सुरक्षा गश्तीदल जब उनका पीछा कर रहा था तो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने उस पर भारतीय प्रदेश में गोली चलाई । ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने स्वचालित हथियारों से करीब 500 गोलियां चलाई और कोई दो घन्टे तक रुक-रुककर गोली चलती रही । हमारी सेना ने बड़े संयम से काम लिया और केवल 138 गोलियां आत्म रक्षा में चलाई । उन्होंने घुसपैठियों के पाकिस्तान में उतरने से पहले ही चोरी का सारा माल बरामद कर लिया ।

(ख) हमारी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ । सीमा सुरक्षा सेना ने तथा त्रिपुरा की राज्य सरकार ने भी पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया । पूर्व-पाकिस्तान की सरकार ने जवाब में विरोध प्रकट किया और यह आरोप लगाया कि भारतीय सीमांत सैनिकों ने पाकिस्तानी पुलिस गश्तीदल पर उस समय गोली चलाई तबकि वह पाकिस्तानी प्रदेश में ही कुछ तस्करों का पीछा कर रहा था, पाकिस्तानी गश्तीदल को आत्म रक्षा में भारतीय सैनिकों पर गोली चलानी पड़ी ।

त्रिपुरा सरकार पाकिस्तान के आरोप का खंडन कर चुकी है और पूर्व पाकिस्तान सरकार से कहा गया है कि यह हमारे विरोध पर कार्यवाही करे जो कि सच्चे तथ्यों पर आधारित है ।

अदन राष्ट्रवादियों की विदेश में प्रस्तावित सरकार

714. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एच० जे० पटेल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदन राष्ट्रवादियों द्वारा विदेश में अपनी सरकार बनाने के प्रस्ताव से संबंधित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है,

(ख) उसका प्रधान कार्यालय कहां होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सरकार को मान्यता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो वहां पर राष्ट्रवादी आन्दोलन को क्या अन्य सहायता देने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अप्रैल 1967 के मध्य में सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी है कि अनधिकृत दक्षिण यमन के मुक्ति मोर्चे के महासचिव, श्री अब्दुलकवी मकावी ने कहा था कि उनका संगठन ताईज़ (यमन) में एक निर्वासित अदेनी सरकार की स्थापना करने पर विचार करेगा ।

(ग) चूंकि निर्वासित सरकार की अभी स्थापना नहीं हुई है, इसलिये भारत सरकार द्वारा उसे मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारत सरकार ने अदन और दक्षिणी अरबिया के लोगों की स्वाधीनता के अधिकार का बराबर समर्थन किया है। हमने यह विचार संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर बराबर व्यक्त किया है। भारत सरकार इस मामले में किये गए अपने निश्चय पर दृढ़ है।

पारपत्र (पासपोर्ट)

715. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1964 से लेकर 1966 के बीच की अवधि में पारपत्र के कितने आवेदनपत्र अस्वीकार किये;

(ख) वे आवेदनपत्र किन कारणों से अस्वीकार किये गये;

(ग) क्या हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार अस्वीकृत आवेदनपत्रों पर पुनः विचार करेगी;

(घ) उपरोक्त अवधि में जाली पारपत्रों के कितने मामले पकड़े गये; और

(ङ) कितने आपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों को विदेशों से भारत में वापिस भेजा गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अमरीकी दूतावासों में भारतीय

716. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अमरीकी दूतावासों में कार्य करने वाले भारतीयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने लोग नई दिल्ली स्थित दूतावास में तथा कितने लोग बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित तीन वाणिज्य दूतावासों में हैं; और

(ग) उनमें से कितने लोग अमरीकी दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावासों, सैनिक सम्भरण मिशन, अमरीकी सूचना सेवा तथा उनके उपकार्यालयों में काम करते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 1680

(ख)	राजदूतावास ...	1131
	प्रधान कौंसलावास, बम्बई ...	180
	प्रधान कौंसलावास, कलकत्ता	210
	प्रधान कौंसलावास, मद्रास ...	168

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय निकास एजेंसी	....	460
भारत में संयुक्त राज्य अमरीका का सैन्य संभरण मिशन	...	35
संयुक्त राज्य सूचना सेवा	...	256
चासरी	...	291
शांति दल	...	5
कांग्रेस पुस्तकालय	....	60
रक्षा सहचारी कार्यालय	...	12
राजदूत निवास	....	12

पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजन

717. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री उमानाथ :
श्री पी० गोपालन :

क्या **गैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय राष्ट्रजन श्री के० पी० आबू (सुपुत्र मुहम्मद कुट्टी हाजि) पाकिस्तानी जेल में नजरबन्द है;

(ख) यदि हां, तो वह कब से नजरबन्द है; और

(ग) सरकार द्वारा उसे रिहा कराने और स्वदेश में जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गैदेशिक कार्य मंत्री (भु० क० चागला): (क) से (ग) जिला पालघाट, गांव वेल्लियनकोडे के निवासी मोहम्मद कुट्टी हाजी के पुत्र श्री के० पी० आबू सन् 1964 से पाकिस्तान में नजरबंद थे । 18 अप्रैल 1967 को वे रिहा कर दिए गए और भारत वापस भेज दिए गए ।

सद्भावना मिशन

718. **श्री एस० आर० दमानी :** क्या **गैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1966-67 में सद्भावना मिशन विदेशों में भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) 1966-67 में जो सद्भावना शिष्टमंडल भेजे गए थे, उनकी एक सूची साथ लगी है । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 423/67**]

Officials of External Affairs Ministry Staying Abroad for Five Years

Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of officers and staff of his Ministry who continue to stay in foreign countries for the last 5 years or more;

(b) the number of such officers who are posted in 'A' class countries only and since how long they continue to stay there;

(c) whether any complaints have been received against such continued postings; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) 277

(b) 7—

One from 1956.
Two from 1959.
Two from 1960.
Two from 1961.
One from January, 1962.

(c) No complaints have been received.

(d) Does not arise.

दिल्ली में जवानों के स्मारक

720. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री के० प्रधानी :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री 27 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सम्बन्ध से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के उन जवानों की स्मृति में, जिन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देश की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, दिल्ली में एक स्मारक बनाने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सविस्तार ब्यौरा क्या है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) । (क) और (ख) : जी नहीं । इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति इस हेतु चुने गए स्थान के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकारी की सैद्धान्तिक रुप से स्वीकृति पाने पर ब्यौरा तैयार करेगी ।

यूनान की नई सरकार को मान्यता

721. **श्री प्र० के० देव :**
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री जी० सी० नायक :
श्री ए० दीपा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनान में सैनिक क्रान्ति के बाद बनी नई सरकार को मान्यता दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक–कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) यूनान की नई सरकार को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हैलेनीस नरेश बराबर राज्य के अधिपति बने हुए हैं और यूनान में सरकार का बदलना एक अन्दरुनी मामला है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के अध्यक्षों के रूप में राजनयिक अधिकारी तथा सार्वजनिक नेता

722. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **वैदेशिक–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनयिक मिशनों के अध्यक्षों के स्तर पर हमारी विदेश सेवा में राजनयिक अधिकारियों तथा सार्वजनिक नेताओं का इस समय क्या अनुपात है;

(ख) विदेशों में हमारे मिशनों के अध्यक्षों के रूप में सार्वजनिक नेताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या दल के सदस्यों में से राजदूत नियुक्त कराने की प्रथा को समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) आजकल 49 वृत्तिक राजनयिक और 15 गैर–वृत्तिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें एक या अधिक में मिशन प्रमुखों के रुप में नियुक्त करके भेजा गया है। 15 गैर–वृत्तिक व्यक्तियों में गैर–सरकारी व्यक्ति, गैर–भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और रिटायर शुदा रक्षा सेवाओं के अधिकारी है।

(ख) और (ग) सरकार अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर विदेशों में मिशन प्रमुखों की नियुक्ति करती है। राजनय में, किसी भी व्यवसाय की तरह, व्यावसायिक व्यक्ति अगर उपयुक्त और सुलभ हों तो, मुख्य रुप से ऐसी जगहों के लिए चुने जाते हैं, हालांकि सरकार विशेष राजनयिक पदों के लिए किसी भी वर्ग में से विशिष्ट प्रमुख व्यक्तियों को मुक्त रुप से चुन सकती है। स्वाधीनता के समय से ही ऐसा होता रहा है। यही चलता रहेगा।

लन्दन में भारतीय उच्च आयोग

723. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लन्दन में भारतीय उच्च आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों तथा उसके व्यय में कमी करने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेश सेवा निरीक्षणालय के अधिकारियों का विचार

भारतीय उच्च आयोग में शीघ्र छटनी करने और व्यय में मितव्ययता लाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लंदन जाने का है;

(ग) भारतीय उच्च आयोग में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उनके वेतनों पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय होती है; और

(घ) मितव्ययता करने से वार्षिक व्यय में कितने प्रतिशत बचत होने की संभावना है ?

गैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) विदेश सेवा निरीक्षालय के एक दल ने विदेश और वित्त मंत्रालयों से एक-एक सह--सचिव, मार्च-अप्रैल 1967 में हाई कमीशन का निरीक्षण पहले ही कर लिया है ।

(ग) विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय हाई कमीशन के विभागों में काम करने वाले लोगों की संख्या 371 है । उनके वेतन और भतों पर होने वाला वार्षिक खर्च क्रमशः 60.19 लाख रुपए और 26.55 लाख रुपए है ।

अन्य मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करने वाले अधिकारियों और अमले के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(घ) किफायत के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट बनाई जा रही है और आशा है कि वह जल्दी ही तैयार हो जायगी ।

आयुध कारखानों में प्रोत्साहन बोनस योजना

724. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में प्रोत्साहन बोनस योजना अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर भी लागू करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा क्योंकि अन्य केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उपलब्ध इसी प्रकार की सुविधाओं के संदर्भ में योजना को अन्य श्रेणियों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा ।

हिमालय क्षेत्र में यूरेनियम के निक्षेप

725. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय क्षेत्र में यूरेनियम के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) क्या बिहार में भी यूरेनियम मिला है; और

(ग) यदि हां, तो विवरण क्या है तथा उनमें अनुमानत: कितना यूरेनियम है ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरूपदस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में यूरेनियम युक्त अयस्क पाई गई हैं। परन्तु अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यह भंडार कितना बड़ा है।

बिहार के सिंगभूम जिले के जादूगुडा में यूरेनियम की एक बड़ी खान खोदी जा रही है। इस जिले में दूसरे स्थानों पर भी निक्षेपों की खोज की जा रही है और उनका विकास किया जा रहा है। यूरेनियम के अब तक पाये गये भंडार ही भविष्य में परमाणु शक्ति परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य-क्रम के लिये पर्याप्त हैं।

शैक्षिक टेलीविजन

726. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान केन्द्र के माध्यम से शिक्षा देने वाले टेलीविजन के लिये एक अग्रिम परियोजना चालू करने की सम्भाव्यता के बारे में भारत सरकार तथा यूनेस्को के बीच विचार विमर्श चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री० के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामला अभी यूनेस्को के विचाराधीन है।

Foreign Correspondents in India.

727. **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) the number of foreign correspondents, along with the names of places in India where they are stationed :

(b) the number of Indian correspondents posted abroad : and

(c) the particulars including their names the newspapers to which they are attached and their nationalities ?

The Minister of External Affairs : (Shri M. C, Chagla) : (a) A statement is placed on the Table of the House. (**Placed in Library, See. No. LT–424/67**). All accredited correspondents are stationed in New Delhi.

(b) and (c) Information is being collected.

1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति प्राप्त अथवा लापता सैनिकों तथा असैनिकों के परिवारों को सहायता

728. मेजर रणजीत सिंह :
श्री वी० एस० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या प्रति रक्षा मंत्री 8 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1599 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत भारत-पाक युद्ध के दौरान ऐसे नागरिकों व सेना कर्मचारियों के परिवारों की जिन्हें लापता अथवा मरा हुआ समझ लिया गया था सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 425/67]**

Prime Minister's visit to Ceylon Question.

729. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister has postponed her programme of visiting Ceylon ;

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) when will it materialise ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) Yes, Sir. The visit had to be postponed due to unforeseen circumstances which made it difficult for the Prime Minister to be away from India during May. She is likely to visit Ceylon later in the year.

पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी जर्मनी से टैंकों की खरीददारी

730. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पश्चिमी जर्मनी से एम-47 किस्म के 600 अमरीकी टैंक, जिनको बोन के सैनिक बल की आवश्यकता नहीं रही है, खरीदने का प्रयास किया है ;

(ख) क्या इस सौदे की ओर अमरीकी सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीकी सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान पश्चिम जर्मनी से अमरीका में बने एम-47 किस्म के

600 टैंक सीधे ही खरीदने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, यह बताया गया है कि पाकिस्तान किसी तीसरे देश को बीच में डालकर पश्चिम जर्मनी से अमरीका में बने एम-47 किस्म के 200 टैंक खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। हमने इस सवाल को संबद्ध सरकारों के साथ उठाया था और यह आशंका प्रकट की थी कि ये टैंक पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। हमारी सूचना के अनुसार यह सौदा नहीं हुआ।

अपंग सैनिकों के लिए आश्रम (होम)

731. **श्री शारदा नन्द :**
श्री जे० बी० सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
मेजर रणजीत सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंग और वृद्ध सैनिकों के लिये आश्रम (होम) स्थापित करने की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) ये आश्रम किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बंगलौर में निर्मित रेडक्रास होम के ही नमूने पर एक आश्रम (होम) उत्तर भारत में बनाए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) उस आश्रम के लिए स्थान और अन्य ब्यौरे अभी तय होने हैं।

पालम हवाई अड्डे से टायर और ट्यूबों की चोरी

732. **श्री शारदा नन्द :**
श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री मेजर रणजीत सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री पालम हवाई अड्डे से टायर तथा ट्यूबों की चोरी के बारे में 20 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर तथा ट्यूबों की चोरी के बारे में इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) मामले की अभी जांच की जा रही है।

(ग) मामले की जांच जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह किस तारीख तक पूरी हो जाएगी।

नागाओं के साथ बातचीत

733. श्री स्वैल :
डा० कर्णीसिंह :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री कीकर सिंह :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री कंवर लाल गुप्त
श्री रास्वरूप विद्यार्थी :
श्री मोहसिन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रा० बरुआ :
श्री एस० के० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की विद्रोही नागा नेताओं के साथ हुई बातचीत में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) समझौता कब तक हो जाने की संभावना है;

(ग) गत छः महीनों में विद्रोही नागाओं ने कितनी हिंसात्मक घटनाएं की हैं;

(घ) क्या विद्रोही नागा नेताओं का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि वे पाकिस्तान से निरन्तर सहायता ले रहे हैं। यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई; और

(ङ) पाकिस्तान से नागाओं को मिलने वाली सहायता को रोकने के लिए क्या सरकार ने कुछ उपाय किये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) छिपे नागाओं के साथ अब तक पांच मौकों पर जो बातचीत हुई है वह खोजकारी प्रकृति की थी। बातचीत में, इस विषय पर भारत सरकार की स्पष्ट स्थिति की पृष्ठभूमि, कि नागालैंड भारत संघ का एक अभिन्न अंग है, सामान्य समझौते के क्षेत्रों का पता लगाने की कोशिश की गई थी। छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों ने उस समय यद्यपि यह कहा था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो रवैया अपनाया है, उससे हटने की स्थिति में वे नहीं हैं, फिर भी, अब तक जो बातचीत हुई है उसकी रोशनी में इस मामले पर पुनः विचार करना उन्होंने स्वीकार कर लिया है और भविष्य में किसी दिन इस मामले पर और आगे बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। शान्तिपूर्ण समाधान खोजने की अपनी इच्छा के अनुरूप, भारत सरकार ने आगे बातचीत करने के लिए अपनी रजामंदी व्यक्त कर दी है।

(ग) 30 अप्रैल 1967 को पूरे होने वाले छह महीनों की वारदातों का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 426/67]**

(घ) जी हां, उन्होंने या तो यह कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है या यह कि इस तरह की कार्यवाइयों में उनका कोई हाथ नहीं है या फिर यह बताया कि यह कुछ गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों का काम है।

(ङ) इस बात की बराबर चौकसी रखी जा रही है कि नागा उपद्रवियों को पाकिस्तान से कोई मदद न मिलने पाए। लेकिन, हमारी हर कोशिश के बावजूद बहुत दुर्गम स्थलों के कारण कुछ लोग चुपचाप पाकिस्तान चले जाते हैं और चले आते हैं।

रोडेशिया

734. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोडेशिया के विरुद्ध कतिपय अनिवार्य पाबन्दियां लागू करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों का पाबन्दियां लागू करने में पश्चिमी देशों के असहयोग के कारण अब तक कोई परिणाम नहीं निकल सका है; और

(ख) यदि हां, तो अफ्रीकी देशों के सहयोग से भारत का विचार क्या कदम उठाने का है जिससे रोडेशिया में श्री स्मिथ के गैर-कानूनी शासन का अन्त हो ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (मु० क० चागला) : (क) दिसम्बर 1966 में सुरक्षा परिषद ने रोडेशिया के खिलाफ जो खास-खास प्रादेशात्मक प्रतिबंध लागू किए थे, उनसे अभी तक वांछित परिणाम नहीं निकल सका है; इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल ने अवैध स्मिथ शासन के विरुद्ध प्रतिबंध लागू करने में सहयोग देने से इन्कार कर दिया है।

(ख) भारत ने हमेशा पूरे दिल से अफ्रीकी देशों की इस मांग का समर्थन किया है कि अगर आर्थिक प्रतिबंध से इस उद्देश्य की प्राप्ति न हो तो ब्रिटेन, जो कि रोडेशिया में संविधानिक शासन पुनः लागू करने के लिए जिम्मेदार है, अवैध शासन को समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग करें। हम इस मांग का निरंतर समर्थन कर रहे हैं। इस प्रश्न पर हमारा व प्रगतिशील अफ्रीकी विचारधारा के पूर्णतया अनुकूल है।

भारतीय राजनयिकों का पेकिंग में स्वागत समारोह से उठ कर चला जाना

735. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1967 को पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पेकिंग में आयोजित समारोह से भारतीय राजनयिक उठ कर चले गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : जी हां।

(ख) 23 मार्च को पेकिंग में पाकिस्तान के राजदूत ने अपने राष्ट्रीय दिवस के समा-

रोह पर स्वागत–सत्कार का जो आयोजन किया था, उसमें से हमारे कार्यनायक, श्री आर० डी० साठे, श्रीमती साठे और राजदूतावास के दो अन्य अधिकारी उठकर बाहर चले आए थे।

इस अवसर पर चीन के विदेश मंत्री, चेन यी, ने अपने भाषण में जब भारत का 'विस्तार-वादी भारतीय प्रतिक्रियावादी' कहकर अपमान किया तब उन्होंने विरोध में ऐसा किया।

Gratuity to Soldiers.

736. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no gratuity is paid to a soldier and only pension is given to him on retirement;

(b) whether it is also a fact that a civilian, on retirement, gets pension as well as gratuity on the basis of his monthly pay;

(c) if so, the reasons therefor: and

(d) the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Gratuity is paid to a soldier, subject to the prescribed conditions, in cases where he has not qualified for a pension. However, it is a fact that a soldier who is entitled to pension gets only the pension and is not given a gratuity in addition.

(b) It is also a fact that a civilian Government servant on retirement with a pension gets the pension Plus a lump-sum gratuity based on his pay.

(c) Prior to 1950, the pension of civilian Government servants was assessed at the scale of 1/60th. of emoluments for each year of qualifying service: and no gratuity was payable in addition. The scale was reduced in 1950 to 1/80th of emoluments: and in addition to the lower pension, the civilian Government servants have been made eligible for a lump-sum gratuity, which represents the capitalised value of the reduction in the pension. In the case of soldiers, the rates of pension laid down are on the basis of the old scale of 1/60th of emoluments (with certain adjustments), and consequently no gratuity can be paid in addition to their pension.

(d) Reduction in the scale for assessing the pension of soldiers, with a view to giving them the benefit of gratuity as well, will result in their getting comparatively very low amounts as pension, because they earn pension after 15 years qualifying service as against 30 years for civilian Government servants. As such, it would not be advantageous to the soldiers if the present system on the civil side is made applicable to them. No action is accordingly proposed to be taken in the matter.

Family Quarters for Armed Forces Personnel in Forward Areas.

737. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether any demand has been made to Government to provide family quarters for the families of those Armed Forces personnel who have been posted in the forward areas and also for making arrangements for the education of their children;

(b) if o, the action taken by Government in this regard; and

(c) whether any other facility is likely to be given to them by Government ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Governmen policy is to provide married accommodation to separated families of officers and other personnel posted to

forward areas, This is normally constructed at places where medical and educational facilities already exist.

Reservation of seats in Military Schools, Lawrence Schools, & Sainik Schools has been provided for children of Defence Services personnel including those serving in forward areas. There are over one hundred Central Schools in the country where children of Defence Services personnel are given first priority for admission.

(b) and (c) Projects for the construction of accommodation for separated families of 1246 officers, 966 JCOs, 3040 Other Ranks and 703 NCs (E) have been sanctioned. Pending construction of sanctioned accommodation for separated families, Government have authorised hiring of houses at selected stations.

बिहार में सहायता कार्यों के लिये सेना की सेवाओं का उपयोग

738. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पाटिल :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री एच० एम० जोशी :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अकालपीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिए सेना की सेवाओं का उपयोग किया गया है;

(ख) सेना ने अब तक क्या विशिष्ट कार्य किए हैं ; और

(ग) क्या सेना की सहायता से कोई नलकूप खोदे गये हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) थल सेना ने विभिन्न क्षमता वाले 14 कुए खोदने में सहायता की है । इन कुओं से पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा । तीन और कुए खोदे जा रहे हैं ।

तीनों सेनाओं से 25 कार्मिकों का एक दल लिया गया जिसमें तीन डाक्टर भी सम्मिलित है । यह दल मई के अन्त से गया जेल में राहत पहुँचाने का काम आरम्भ करेगा और एक मुफ्त भोजनालय भी चलाएगा जिसमें प्रतिदिन लगभग 500 मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी ।

Advertisements in Newspapers.

739. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of newspapers published in English and Indian Languages in the country, separately: and

(b) the total value of advertisements given by Government to these newspapers, separately, during the year 1966-67 ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The requisite information is given below in respect of newspapers which include periodicals.

Languages	No. of newspapers and periodicals published in the country.	Total value of advertisements released through DAVP during 1966-67.
		Rs.
English	2,356	45,32,188
Hindi	2,276	9,38,913
Assamese	33	49,124
Bengali	604	4,67,715
Gujarati	622	2,99,671
Kannada	254	1,02,007
Malayalam	300	2,97,938
Marathi	543	2,94,240
Oriya	89	60,308
Punjabi	199	1,22,210
Sanskrit	31	—
Tamil	447	1,98,381
Telugu	328	1,30,334
Urdu	900	2,70,573
Sindhi	65	14,278

ढाका में भारतीय उच्च आयुक्त

740. श्री स्वैल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारतीय उच्चायुक्त की उपस्थिति में ढाका, पूर्वी पाकिस्तान में उनके होटल के कमरे में लगा हुआ जासूसी करने का यंत्र पकड़ा गया ;

(ख) क्या उच्च आयुक्त से कोई रिपोर्ट मांगी गई है ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कुछ अखबारी रिपोर्ट के अनुसार टेलीफोन के मिस्तिरी लोग हाई कमिश्नर के कमरे में, जहां वह ठहरे हुए थे, जाहिरा तौर पर इस इरादे से आए कि वहां पर रखे टेलीफोनों की जांच कर ली जाय और वे लोग नीचे की मंज़िलों में ठीक उसके नीचे के कमरों में भी कुछ ठीक-ठाक करने की गरज़ से गए लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि हाई कमिश्नर महोदय पहिले ही पहुँच चुके थे और वहां मौजूद थे।

(ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तान-स्थित हमारे मिशनों का ख्याल है कि मिशन अधिकारियों की टेलीफोन पर की जाने वाली बातचीत को नियमित रूप से सुना जाता है। पाकिस्तान सरकार के पास विरोध-पत्र भेज दिया गया है ।

सैनिक आवास-बस्तियां

741. श्री हेमराज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी सैनिक आवास बस्तियां बसाने का विचार है और जिन स्थानों पर इन्हें बसाया जायेगा, उनके नाम क्या है;

(ख) इस प्रकार बसाई जाने वाली बस्तियों की संख्या कितनी है और जिन व्यक्तियों को उनमें बसाया गया है उनकी संख्या क्या है ;

(ग) पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में सैनिक बस्ती स्थापित करने में क्या प्रगति की गई है; और

(घ) इसका निर्माण कब आरम्भ करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) देश भर में सैनिक आवास बस्तियां स्थापित करने की योजना के पहले चरण के लिये दिल्ली के अलावा 60 केन्द्र चुने गये हैं। उनकी एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 427/67]**

(ख) सदस्यों से इकट्ठे किये गये धन से देहरादून और गोआ में भूमि का अर्जन किया गया है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने चण्डीगढ़ में 800 विकसित प्लाट देने का वचन दिया है।

(ग) और (घ) अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और यह बताना समम्व नहीं है कि पालमपुर में सैनिक बस्ति कब स्थापित हो जायेगी।

पाकिस्तान के रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार

743. प्रो० समर गुह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने रेडियो से भारत विरोधी प्रचार हाल ही में तीव्र कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान रेडियो का प्रचार काश्मीर प्रश्न पर केन्द्रित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान के प्रचार का निराकरण करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार हर प्रकार के पाकिस्तान-विरोधी प्रचार से दूर रही है, खासकर इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं ताशकन्द की भावना भंग न हो जाये। फिर भी पाकिस्तान रेडियो द्वारा किये गये झूठे प्रचार को निष्फल करने के लिये सरकार स्वभावत: कदम उठाती रही है। आकाशवाणी पाकिस्तान द्वारा प्रचारित शरारत भरे वक्तव्यों और झूठी खबरों का विश्लेषण करते हुये, विभिन्न भाषाओं में नियमित समाचार-समीक्षायें और वार्तायें प्रसारित करती है।

परमाणु इंजीनियरी

744. प्रो० समर गुह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा परमाणु शस्त्र बनाने की वांछनीयता के प्रश्न को अलग रखते हुए क्या

सरकार यह आवश्यक समझती है कि भारत को परमाणु इंजीनियरी का औद्योगिकी विकास करने के लिए अन्य देशों से पीछे नहीं रहना चाहिए; और

(ख) परमाणु इंजीनियरी के विकास में सबके साथ प्रगति करने के लिए और परमाणु की विस्फोटक शक्ति का शान्तिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए क्या सरकार को परमाणु शक्ति आयोग को आदेश देने चाहिए कि वह भारत में उपलब्ध तथा तैयार होने वाले परमाणु इंधन के विखण्डन के लिए भूमिगत प्रयोगात्मक कार्य करे ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदीस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। हमारा यह निश्चय है कि हम परमाणु शक्ति का शान्ति के उद्देश्यों के लिये उपयोग करने सम्बन्धी वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। परमाणु शक्ति आयोग इस उद्देश्य के अनुरुप प्रयोग कार्य से सम्बन्धित सभी पहलुओं का निरन्तर पुर्नावलोकन करता रहता है।

इस्लामी देशों का आर्थिक गुट

745. **श्री बलराज मधोक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अपने देश, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब तथा जोर्डन का एक इस्लामी आर्थिक गुट स्थापित करने की योजना बना रहा है ;

(ख) क्या इस प्रस्तावित आर्थिक ब्लाक के बाद सेटो से बाहर इन्हीं देशों का एक सैनिक गुट बनाया जायेगा।

(ग) क्या सरकार ने भारत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का गुट बनाने से पैदा होने वाली बातों का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस नये अभियान का निराकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता और सहयोग करने की बात कही है।

(ख) पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के बीच सैनिक गुट बनाने के बारे में कहीं कुछ चर्चा तो हुई है, लेकिन भारत सरकार इस तरह का गुट बनाने की सूचना की पुष्टि प्राप्त कर सकी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार इस संबंध में घनटाओं पर निगाह रखे हुए है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रतिरक्षा पर व्यय

746. श्री शिवचन्द्र झा : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पन्द्रह वर्षों में भारत का प्रति व्यक्ति प्रतिरक्षा व्यय पाकिस्तान के व्यय के मुकाबले में कुल मिला कर कम रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को हाल में मिली अमरीकी सहायता से भारत के व्यय के मुकाबले पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : मुझे बहुत खेद है कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में सम्बन्धित ठीक आकड़ों की नामौजूदगी में इस प्रश्न पर निश्चित–रुप से कुछ कहा नहीं जा सकता । जहां तक हम पाकिस्तानी आकड़ों का अनुमान लगा सकते हैं स्थिति इस प्रकार है कि पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति प्रतिरक्षा व्यय हमारे व्यय के मुकाबले अधिक है । पाकिस्तानी प्रतिरक्षा बजट पर हाल के अमरीकी घोषणा से क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता ।

भारतीय नौसेना के भण्डारों में सामान देने की प्रणाली

747. श्री ए० श्रीधरण : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय नौसेना के भण्डारों में सामान देने की प्रणाली में त्रुटियों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये त्रुटियां कैसी है और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान निम्नलिखित त्रुटियों की ओर दिलाया गया है :

(1) नौसेना के भण्डारों की उपलब्धि में विलम्ब । इन भण्डारों के लिए ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्रालय (नौसेना) को आर्डर दिया गया था लेकिन उन्होंने उन भण्डारों को सुपुर्द करने की तारीख अभी नहीं बताई है । इससे भण्डारों की प्राप्ति पर पूरी तरह से उनका उपयोग नहीं हो सकेगा ।

(2) कुछ मामलों में देशी भण्डारों की व्यवस्था के लिए अवास्तविक अनुमान । इन त्रुटियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :--

(1) ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को केवल वर्गीकृत मदों के लिए या ऐसे सामान के लिए जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा लाइसेन्स के अधीन बनाए जाते हैं । या फिर जो उनके फालतू भंडारों से रियायती कीमतों पर उपलब्ध हैं, इन्डेन्ट भेजे गए हैं । अन्य इंडेंट लन्दन में इण्डिया सप्लाई मिशन को भेजे गए हैं जो निश्चित सुपुर्दगी की तारीख के साथ करारनामे पर हस्ताक्षर करते हैं ।

(2) ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि आवश्यकताओं को निर्धारित करने से पूर्व भण्डारों पर संम्भाव्य व्यय को अधिक सावधानी से निर्धारित किया जाय।

उड़ीसा में सैनिक स्कूल

748. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों को अपर्याप्त भोजन देने और पहनने के तथा अन्य उचित वस्त्रों की कमी के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के संरक्षकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) उड़ीसा में सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पहनने के तथा अन्य उचित वस्त्रों की व्यवस्था में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सैनिक स्कूल समिति के गवर्नरों के बोर्ड की पिछली बैठक में उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि ने 2 रूपये की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वर्तमान खुराक को अपर्याप्त बताया। बोर्ड ने यह अनुभव किया कि अन्य पब्लिक स्कूलों में सामान्यरूप से उपलब्ध खुराक और कीमत के स्तर की यह एक सामान्य समस्या है। तदनुसार यह निर्णय किया गया कि अन्य पब्लिक स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए सैनिक स्कूलों में उपलब्ध खुराक के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जाय और उसके परिणामों को डाक्टरी अनुसन्धान भारतीय परिषद को इस सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए भेजा जाय। सर्वेक्षण के पूरे होने पर, जो इस समय किया जा रहा है, निर्णय लिया जाएगा और तब डाक्टरी अनुसंधान भारतीय परिषद की सलाह ली जाएगी।

भूतान में भारतीय

749. **श्री शिवपूजन शास्त्री :**
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक–कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रायपुर से प्रकाशित 5 मई, 1967 के 'युग धर्म' में भूतान में भारतीयों के साथ हुए दुर्व्यवहार के समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो किन अधिकारियों ने उक्त दु:खभरी कहानियां सुनाई;

(ग) क्या वास्तविक तथ्य तथा जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) रिपोर्ट कहां तक ठीक है, इसका पता लगाने के लिए सरकार ने पूछ ताछ शुरू कर दी है।

Hindi News Room.

750. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to popularise Hindi, Government propose to set up a 'Hindi News Room' like an English one so that news may be obtained in Hindi:

(b) if so, the progress made so far in this regard; and

(c) when it would start functioning ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) At present, the main sources of news are the two news agencies Press Trust of India and the United News of India. They issue their material in English. We are also receiving Hindi service on an experimental basis. The question of subscribing to a Hindi news agency is under active consideration.

2. Short of setting up a separate Hindi News Room, which at present is not a practical proposition, steps have been taken to increasingly prepare material for Hindi news bulletins and commentaries directly in that language. At present, all Hindi talks and commentaries are prepared directly in Hindi, and a major proportion of the daily news bulletins is prepared directly in Hindi. Steps are being taken to accelerate the process for ultimately setting up a "Hindi Newsroom" subject to availability of resources.

किट्टूर (मैसूर) में सैनिक स्कूल

751. श्री एस० ए० अगाड़ी : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जी ने मैसूर राज्य के जिला बेलगांव में किट्टूर में लड़कियों के रानी चेनम्मा सैनिक स्कूल की आधार शिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो आधार शिला किस तारीख को रखी गई थी;

(ग) यह योजना किस तारीख को मंजूर की गई थी और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्कूल के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) 10 जनवरी 1967 को प्रधान मंत्री ने मैसूर राज्य के जिला बेलगांव में किट्टूर में लड़कियों के रानी चेनम्मा सैनिक स्कूल की आधार शिला रखी थी। यह स्कूल राज्य सरकार की एक प्रायोजना है जिसका सैनिक स्कूल संस्था द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल राज्य सरकार से है।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड, दरभंगा

753. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा के सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं और यह बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को योजनाबद्ध तरीकों से सहायता प्रदान नहीं करता; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि इस बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। फिर भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि यह बोर्ड योजनाबद्ध तरीकों से भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता नहीं करता ।

(ख) इस मामले को आवश्यक कार्यवाही हेतु सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड, बिहार के ध्यान में लाया जाएगा ।

RADIO PROGRAMMES ON CULTIVATION

754. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the nature of schemes prepared by All Indi Radio to broadcast information regarding methods of intensive cultivation, the manner in which seeds, fertilizers, insecticides and farm implements are to be obtained as also the places from where these are obtainable and about the mode and time of irrigation ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : Ten Farm and Home broadcasting units were established during the year 1966-67 at ten stations to give active support to the intensive agricultural and highy-yielding varieties programme of the Ministry of Food and Agriculture at the Centre and the State Agriculture Departments in the field. These units have been set up to cater to the needs of a small, compact and homogeneous agricultural area selected on the basis of similarity of practices and problems. The programmes have been mostly field-based and problem-oriented and a large number of progressive farmers are now participating in the broadcasts. This is going a long way in establishing a two-way traffic between the All India Radio stations on the one side and the farmers on the other.

2. Six more intensive Farm and Home Units are proposed to be established during the current year bringing the total number of units to 16. These 16 units will cover an area of 32.5 million acres in about 130 districts during the current Plan period.

3. The main objective of the Farm and Home units is to disseminate information in support of intensive cultivation and high-yielding varieties programmes involving the use of better quality seeds, fertilizers, insecticides and improved farm implements. The question of their availability is dealt with in general in these programmes and specific information in this regard is supplied to the farmers by the extension agencies of the States. The mode and time of irrigation as advocated in the package of practices in respect of various crops also form an important part of all programmes.

A bi-weekly programme for the agriculturists of the Union Territory of Delhi has been started from the Delhi Television Centre since January 26, 1967. Eighty Television Sets have been installed in the villages and the programmes mainly concentrate on educating and informing the cultivators about intensive cultivation programmes and high-yielding varieties.

A. I. R. Station at Raxaul

755. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to establish a ten Kilowat broadcasting station at Raxaul on the Indo-Nepal border ;

(b) if so, the action being taken in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) This area is already being served by the Medium Wave transmitter at Patna. The coverage on the Indo-Nepal Border is proposed to be further increased under the 4th Plan by installation of a Medium Wave transmitter at Darbhanga, and a high power transmitter at Gorakhpur.

Correspondence with Foreign Countries in Hindi

756. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that correspondence with foreign countries is not done in Hindi because people there have hardly any knowledge of Hindi ;

(b) whether Government have made arrangements to send both Hindi and English versions of their letters to the foreign countries;

(c) if so, the number of such letters sent between July, 1966 and February, 1967 ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. Except for formal communication like letters of credence, our missions abroad do not correspond with foreign countries in Hindi, primarily because people there have hardly any knowledge of Hindi, but also because we are short of personnel with adequate knowledge of Hindi and the ability to express themselves in Hindi as precisely as in English. For the same reason English continues to be largely in use in the Ministry of External Affairs itself.

(b) No, Sir. In the above mentioned circumstances, no purpose will be served at the present stage by sending a Hindi version with an English text; on the other hand it will involve us in avoidable expenditure in foreign exchange on staff and other requisites.

(c) and (d) : Do not arise.

Publication of Books of Military Personnel

757. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Goverment have formulated any code of conduct for retired military personnel in regard to publishing of books containing official secrets from the view point of National security; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir. Retired military personnel are liable to be dealt with in the same way as other citizens, for violation of the official Secrets Act. The general question whether retired Service personnal should be precluded from writing books etc., without obtaining prior approval of Government is, however, under consideration.

(b) Does not arise

सहकारी आधार पर समाचार पत्र

758. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आधार पर सहकारी समाचार पत्रों की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन समाचार पत्रों को कितनी सहायता देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) समाचार-पत्रों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं; परन्तु यदि निजी उद्यम के बल पर इस प्रकार की संस्थाएं बनाई जाएं, तो सरकार उन्हें अखबारी कागज का कोटा, विज्ञापन, संवाददाताओं को मान्यता, दूर-संचार सुविधाएं, आदि के रूप में आवश्यक सहायता देने के लिए बिल्कुल तैयार है, ताकि इस प्रकार की संस्थाओं की वृद्धि को प्रोत्साहन मिले ।

सैनिक कृषि फार्म, काशीपुर

759. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला नैनीताल के काशीपुर में चलाये जा रहे सैनिक कृषि फार्म में पिछले तीन वर्ष की अवधि में कितना लाभ हानि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारी लोग स्थानीय किसानों से साझेदारी के आधार पर और इस आधार पर काम करवाते हैं कि स्वयं खेती नहीं करवायेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस फार्म की काफी जमीनें कांस घास के कारण बंजर पड़ गई है और बेकार हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) काशीपुर में कोई सैनिक कृषि फार्म नहीं है । काशीपुर से लगभग मील की दूरी पर हेमपुर में एक रिमांउड ट्रेनिंग स्कूल और डिपू है । वहाँ पर पशुओं रखने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक यूनिट है, जो व्यापारिक यूनिट नहीं है । मार्च 1966 से जनवरी 1967 तक इस यूनिट के लिए भूमि अधिगृहीत की गई । पिछले में कितना लाभ/हानि हुई, यह नहीं बताया जा सकता है ।

(ख) डेला नदी के पास कुल 4015.78 एकड़ भूमि में से लगभग 250 एकड़ भूमि वटाई पर या वटाईदार आधार पर दी गई है । शेष भूमि रिमांउट ट्रेनिंग तथा डिपू प्राधिकारियों के इस्तेमाल में है ।

(ग) कांस घास की उत्पत्ति के कारण कहीं भी भूमि को बंजर या बेकार नहीं रखा गया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Pony Breeding Centre, Babugarh (U. P.)

760. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) the number of ponies reared at the Government Pony Breeding Centre, Babugarh in Meerut District, Uttar Pradesh and the expenditure incurred thereon so far ;

(b) the percentage of Defence requirement being met by this Centre; and

(c) the source from which the remaining requirement is met ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) the pony youngstock produced at the Equine Breeding Stud, Babugarh, veries from year to year and was 134 during 1966-67. Separate figures of expenditure in respect of the pony youngstock are not maintained.

(b) 44.6%.

(c) By purchases from breeding areas and by production at the Equine Breeding Studs of Saharanpur and Hissar.

Broadcast By M. Ps.

761. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state;

(a) the number of Members of Parliament by whom talks were broadcast from the Delhi Station of All India Radio from January 1967 to date; and

(b) the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) 19Members of Parliament broadcast from Delhi Station of All India Radio from the 1st January, 1967 to 23rd May, 1967.

(b) A statement is laid on the table of the House. **(Placed in Library, See No. LT-428/67)**

भारत से ब्रिटेन जाने वाले भारतीय लोगों के बारे में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ बातचीत

762. **श्री मोहसिन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले भारतीय लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में ब्रिटेन के उच्चायुक्त और उनके बीच हाल में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) विदेश मंत्री के कहने पर इस मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय आप्रवासियों की कठिनाइयों का प्रश्न हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर के साथ उठाया था। उन्होंने इस मामले को अपनी सरकार के पास भेजने का वादा किया है और यह भी कि मिलने पर हमें उसके विचारों से अवगत करा दिया जाएगा। उनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान-नागालैंड-नेफा ब्लाक के बारे में सी० आई० ए० की योजना

763. **श्री याज्ञिक :** क्या **गैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं के केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण (सी० आई० ए०) को इस योजना के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीन के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली ढंग से अभियान करने के हेतु पूर्वी पाकिस्तान, नागालैंड और नेफा का एक गुट बनाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है जिनमें पूर्व पाकिस्तान के दो नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि सी० आई० ए० पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल और असम को मिलाकर एक ब्लाक बनाने की साजिश कर रही है, जिसका नाम 'बंगसम' होगा यह उस बड़ी योजना का अंग है जिसका संबंध चीन के चारों तरफ आकाश तथा जमीन पर मजबूत अड्डे स्थापित करने से है। सरकार को इस कथित योजना की आधिकारिकता के बारे में पुष्टि नहीं प्राप्त हुई है।

दिसम्बर 1966 और जनवरी 1967 में पाकिस्तानी अखबारों में भी इसी तरह की खबरें छपी थी कि पश्चिमी राष्ट्रों की यह कथित साजिश है कि तथाकथित 'संयुक्त राज्य बंगाल' की स्थापना की जाय जिसमें पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और भूटान हो। ये रिपोर्ट निराधार साबित हुई।

अगर वास्तव में इस तरह का कोई आधार हो, तो भी सरकार स्वभावतः ऐसी किसी भी बात को निंदा करती है।

बड़ौदा में भूमि का अर्जन

765. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा में अलेम्बिया वर्क्स के निकट एक ऊपरी पुल बनाने के लिये बड़ौदा नगर निगम ने उनके मंत्रालय के कब्जे में पड़े एक जमीन के टुकड़े को अर्जित करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है।

(ख) क्या ब्रिटिश उच्च आयुक्त ने भूमि के इस टुकड़े के लिये कोई आपत्ति नहीं का प्रमाण पत्र दे दिया है क्योंकि इस भूमि पर ब्रिटिश हाई कमीशन को अलाट किया गया एक कब्रिस्तान है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस भूमि को पुल के लिये अर्जित करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बड़ौदा नगर निगम से ब्रिटिश उच्च आयुक्त के जरिये मार्च 1967 में ऊपरी रेलवे पुल बनाने के लिए "बड़ौदा गवर्नमेंट सीमेन्ट्री" के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र से भूमि का एक टुकड़ा लेने के लिए प्रार्थना पत्र मिला था।

(ख) बड़ौदा नगर निगम के साथ स्वीकृत शर्तों पर ब्रिटिश उच्च आयुक्त ने कब्रिस्तान की भूमि को प्रस्तावित रेलवे के ऊपरी पुल को बनाने के लिए "कोई आपत्ति नहीं" का प्रमाण पत्र दे दिया है।

(ग) सम्बन्धित भूमि सरकार की है इसलिए भूमि अर्जन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि उल्लिखित शर्तों पर प्रस्तावित ऊपरी पुल बनाए जाने पर रक्षा मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच तनाव

766. श्री महाराज सिंह भारती :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या उनके हाल के अरब देशों के दौरे के समय सिरिया–इजराइल समस्या पर कोई विचार–विमर्श किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) अपने हाल के दौरे में मैंने दो दिन कुवैत में बिताए और रास्ते में बेरूत और बगदाद में रुका। अरब नेताओं के साथ अरब–इसराईल के मामलों पर जो बातचीत हुई थी वह वर्तमान संकट के संदर्भ में नहीं थी ; यह संकट तो बाद में खड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में जो गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है उस पर भारत सरकार को अत्यधिक चिंता है तथा वह इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयत्नों का पूरी तरह समर्थन करती है।

गोहाटी आसाम के लिये अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर

767. श्री बेदव्रत बरुआ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान अक्षम ट्रांसमीटरों के स्थान पर गौहाटी में शीघ्र ही एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसकी क्षमता कितने किलोवाट की होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। गौहाटी में आवश्यक क्षमता के काफी ट्रांसमीटर हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Land Reform Law of Nepal

768. **Shri Gumanad Thakur** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 764 regarding the New Land Reform Law of Nepal on the 7th November, 1966 and state;

(a) whether reply from the Government of Nepal on the subject of legislation enacted by that Government barring registration of land in the name of foreigners has since been received;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the action taken by the Government thereon ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) subseqent to the reply given on 7th November, 1966, a statement was made by the then Minister of State in the Ministry of External Affairs on Land Legislation in Nepal as in affects Indians there; they are the only foreigners in Nepal with whom the Government of India are concerned. After the statement the general issue has been under discussion with His Majesty's Government of Nepal who have a sumpathetic Understanding of the issue. In the connected matter of citizenship, His Majesty's Government of Nepal, by an Ordinance issued recently, have taken steps which will assist people of Indian origin in acquiring Nepali citizenship. The Government of India are deeply appreciative of this gesture and have every hope that His Majesty's Government of Nepal will also authorise action to remove disabilities of Indian nationals which have arisen under Land Legislation in Nepal in recent years.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल में घेराव के मामले में केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री का हस्तक्षेप

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : On a point of Order, Sir. I had also tabled a calling Attention Notice on this very subject. I should be allowed to move this motion or else, my name should also be included as on of the movers.

अध्यक्ष महोदय : जब तो नाम इसमें शामिल नहीं किया जा सकता । मैं इन मामले की जाँच करूंगा ।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Alleged interference by Union Home Minister in regard to 'Gheraos' in West Bengal".

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जैसा कि सदस्यों को पता है, पिछले मार्च के शुरू से ही घेराओं बड़ी संख्या में किये जा रहे हैं और उनमें से अधिक पश्चिमी बंगाल में किये गये हैं । इस प्रकार के कुछ मामले अन्य राज्यों में भी हुए हैं । ऐसे घेराओं में निरीक्षक कर्मचारियों, प्रबन्धकों और दूसरे कर्मचारियों को अनुचित रूप में रोका जाता है । भारतीय दंड संहिता में यह मामले हस्तक्षेप अपराध माने गये हैं, पश्चिमी बंगाल में घेराओं के कुछ मामले केन्द्रीय सरकार के विभागीय अथवा निगमित संस्थानों तथा उपक्रमों में हुए हैं ।

हमें मालूम हुआ कि कुछ राजनैतिक दल तथा कार्मिक संघ श्रमिक निधियों के अधीन शिकायतें दूर कराने की बजाय विधि से अपने हाथ में लेने के लिए कर्मचारियों को उकसाते हैं। यह भी पता चला है कि विभिन्न कारणों से पुलिस घेराओं में आने वाले नागरिकों का संरक्षण नहीं कर सकी है, यद्यपि उनका संरक्षण करना पुलिस का कर्तव्य है। ऐसी घटनाओं से जनता में चिन्ता और केन्द्रीय सरकार को शंका पैदा हो गई है।

जब मैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सम्मिलित होने के लिए 18 तथा 19 मई, 1967 को कलकत्ता गया तब मुझे पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से इस विषय पर बातचीत करने का अवसर मिला। पहले भी मैंने मुख्य मंत्री से बातचीत की थी तथा उन्हें पत्र लिखा था। उनके अतिरिक्त यह मामला इतना महत्वपूर्ण था। कि मैंने उस बैठक में कहा कि घेराओं जब छिटपुट अनायास तथा थोड़ी अवधि का प्रदर्शन न हीं रहा बल्कि इसने डर तथा असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है, हम छटनी और अनिवार्य अवकाश आदि में पैदा होने वाली कठिनाइयों तथा श्रमिकों की समस्याओं को जानते हैं। हमें उनके साथ पूरी पूरी सहानुभूति है किन्तु आर्थिक तथा मानवीय समस्याओं का हल शान्तिपूर्ण तथा सहकारी रूप से करना होगा। हमें हर हालत में संविधान तथा विधि के शासन की मर्यादा बनाये रखनी होगी। आशा है कि विधि के शासन का और अधिक उल्लंघन नहीं किया जायेगा। मालिकों तथा कर्मचारियों में आपस में मेलजोल पैदा करके औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के समाधान के तरीके निकालने की दिशा में की गई राज्य सरकार की कार्यवाही से शीघ्र ही कोई परिणाम निकलेगा।

यह बात उचित नहीं है कि संविधान तथा विधि की मर्यादा बनाये रखने की प्रार्थना तथा परामर्श को राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप समझा जाये। यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा न करती तो वह संविधान के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों तथा जिम्मेवारियों को पूरा करने में असफल रही।

श्री हौ० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : किसी मामले के प्रति उल्लेख करना सरकार के लिए उचित नहीं है, जिसका सम्बन्ध किसी विशेष राज्य सरकार से हो और जो इस सभा में अपना पक्ष प्रस्तुत न कर सकती हो। इस सभा में राज्य सरकार से सम्बन्धित विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। घेराओं सम्बन्धी यह मामला न्यायालय के विचाराधीन भी है। उसे ध्यान में रखते हुए संसद में उस पर विचार करना बिलकुल अवांछनीय है। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को उठाने की अनुमति दे दी है। हमने इस प्रश्न पर विचार किया था, कि क्या उस पर इस सदन में चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं। यह विचार करने के बाद ही इसे स्वीकार किया गया था। यहां किसी विशेष घेराओं के मामले का उल्लेख नहीं किया जायेगा, बल्कि घेराओं के विषय पर सामान्य रूप से चर्चा की जायेगी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : पहले जब भी हम इस सभा में कोई ऐसा मामला उठाने का प्रयत्न करते थे जिसका सम्बन्ध जनता से हो तो हमें यह कहकर ऐसा मामला उठाने से रोक दिया जाता था कि यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है। घेराओं राज्य का मामला है और अवश्य ही विधि तथा व्यवस्था का विषय है। यदि इसका अर्थ यह है कि अब संसार विधि

तथा व्यवस्था के मामलों पर विचार कर सकेगी तो मैं इसका स्वागत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : हम राज्य में विधि तथा व्यवस्था के विषय पर चर्चा नहीं कर रहे, न ही हम घेराओं पर चर्चा कर रहे हैं । यह चर्चा गृह–कार्य मंत्री के राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप के आरोप के बारे में है । इसलिए, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : घेराओं विधि तथा व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि यह एक कार्मिक संघों सम्बन्धी मामला है । इस पर दो घंटे की चर्चा की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पहलू पर भी विचार नहीं कर रहे हैं । हम घेराओं के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे । हम केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या माननीय गृह–कार्य मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है ?

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : गृह–कार्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कहा है, वह ठीक है । प्रधान मंत्री को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव में घेराओं के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री द्वारा कथित आरोप का मामला उठाया गया है । इस सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने हस्तक्षेप किया है अथवा नहीं । मंत्री महोदय को 'हां' अथवा 'न' में उत्तर देना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सदन को इस बात का निर्णय गृह–कार्य मंत्री के वक्तव्य के अनुसार करना है कि उन्होंने हस्तक्षेप किया है अथवा नहीं । घेराओं की समस्या का श्रमिकों से सम्बन्धित पहलू भी है । इसका विधि तथा व्यवस्था का पहलू भी हो सकता है । यदि मंत्री महोदय ने कलकत्ता अथवा बंगाल में घेराओं के किसी विशेष मामले का उल्लेख किया होता तो भी बात समझ में आ सकती थी परन्तु वह तो घेराओं के सम्बन्ध में सामान्य रूप से बात कर रहे थे, जब तक माननीय मंत्री यह न सिद्ध करें कि यह मामला मुख्य रूप से विधि तथा व्यवस्था का मामला है और यह श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है तब तक गृह–कार्य मंत्री इस मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकते ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं । इनका कोई लाभ नहीं है । इनके उत्तर नहीं दिये जायेंगे ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : हम घेराओं का अर्थ जानना चाहते हैं । यदि एक व्यक्ति अपनी मांग के सम्बन्ध में जाता है तो इसे प्रार्थना कहते हैं । यदि हो जायें तो अभ्यावेदन कहते हैं । यदि चार जायें तो उसे प्रतिनिधिमण्डल कहा जाता है और यदि 180 व्यक्ति जायें तो इसे घेराओं कहा जाता है, इसमें बिधि तथा व्यवस्था का कौनसा मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका ठीक उत्तर आप श्री डांगे से सदन के बाहर ले सकते हैं ।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Did the Minister of Home Affairs try to take the chief Minister of West Bengal into confidence before issuing the statement to the press ? May I know whether there has been any increase or decrease in the cases of Gheraos after this statement was issued ? Will the hon. Minister be pleased to state there is any alternative to Gheraos for the solution of labour problems

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वक्तव्य जारी करने वाले दिन ही मैंने बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत की थी। उससे पहिले मैंने उन्हें पत्र भी लिखा था। घेराओं के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसलिए घेराओं अभी तक जारी हैं। किसी भी आर्थिक समस्या का हल शान्तिपूर्ण ढंग से होना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The subject of law and order is included in part 2 of the Schedule and it is, therefore, a state subject. I would, therefore, like to know, under which Article of the Constitution he has given direction or advice to the State Government.

I would also like to know from the hon. Minister whether the State Governments should resort to lathi charge if the labourers resort to Gheraos or Dharna against any injustice meted out to them by the employers.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने जो कुछ कहा है, माननीय सदस्य ने उसे गलत समझा है। कोई आदेश देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। परन्तु संविधान के अन्तर्गत संघ तथा राज्य सरकार दोनों पर ज़िम्मेदारियां हैं और जब इस प्रकार की समस्यायें पैदा होती हैं तो राज्य सरकार को प्रार्थना करना मेरा कर्त्तव्य है।

Shri Madhu Limaye : You should also inform under which provision of the Constitution he has interfered in this matter.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की यह ज़िम्मेवारी है कि वह देखे कि संसद के द्वारा पारित अधिनियम तथा उस समय लागू अधिनियम लागू रहें और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार हो कि उन विधियों का पालन हो। भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता ऐसी ही विधियां हैं। जब हमने देखा कि हस्तक्षेप्य अपराधों के बारे में कार्यवाही नहीं की गई, तो मेरा यह कर्त्तव्य था कि राज्य सरकार को निवेदन करूं ..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री अ० क० गोपालन : (**कासरगोड**) : क्या मैं जान सकता हूं कि गृह-कार्य मंत्री ने पूर्वी खण्ड परिषद (जोनल काउन्सिल) में, जिसके वह सभापति थे, अपने आरम्भिक भाषण में घेराओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा परन्तु अपने अन्तिम भाषण में उन्होंने नरेशों के बारे में आकस्मिक ही कुछ बातें कहीं। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा परन्तु बाद में समाचार पत्रों के संवाददाताओं के समक्ष इस विषय को ही मुख्य विषय बनाया। उसके बाद हावड़ा में एक बुरी घटना हुई। पश्चिमी बंगाल के विधि तथा भूराजस्व मंत्री, श्री हरि कृष्ण कोनार ने कहा कि मंत्रियों के समक्ष पुलिस वालों ने लोगों को पीटना आरम्भ कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्भव है कि केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री के भाषण से पुलिस के प्रतिक्रियावादी अफसरों को प्रोत्साहन मिला हो।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय मंत्री ने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, उनका मेरे वक्तव्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने अन्तिम भाषण में इसका उल्लेख किया था और इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। यह भाषण पहले से तैयार किया गया था।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : इस मामले का एक और पहलू संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस मामले में हमारी रक्षा कौन करेगा ?

श्री नायनार : (पालघाट) : गृह-कार्य मंत्री ने यह कहकर, कि संविधान के अन्तर्गत पुलिस ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, बंगाल पुलिस को बंगाल सरकार के विरुद्ध उत्साहित किया है। में यह जानना चाहता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के संवैधानिक पहलुओं के बारे में संविधान में क्या उपबन्ध है। यदि यह मामला विधि तथा व्यवस्था से सम्बन्धित है तो इसके बारे में सूचना देना राज्यपाल का काम है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कहना बिलकुल बेहूदा बात है कि मैंने पुलिस को उत्तेजित किया है।

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : घेराओ, वैध हड़ताल अथवा सत्याग्रह है। इस संघर्ष की निन्दा करके मंत्री प्रबन्धकों का पक्ष ले रहे हैं तथा पुलिस को सरकार के विरुद्ध उकसा रहे हैं।

मंत्रियों के बिड़ला बन्धुओं से वेतन पाने के आरोप के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला

Matter under Rule 377 re : Allegations against Ministers being in pay of Birlas

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि मंत्री-मण्डल के एक अथवा एक से अधिक सदस्य बिड़ला से वेतन प्राप्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है श्री मधु लिमये ने भी इस बारे में लिखा था। मैं कल ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति दे रहा हूँ। आशा है कि कल कुछ सूचना दी जा सकेगी।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGE

पहला प्रतिवेदन

Motion re: First Report of

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I beg to move :—"That the First Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 22nd May, 1967, be taken into consideration".

As the House is aware that an hon. Member of this House Swami Brahma Nand was arrested on the 5th April in front of Parliament House. The Police authorities

should have informed you and through you to the House under the Rule Nos. 229 and 230. The District Officer has failed in doing his duty. The hon. Home Minister had stated that Swamiji was not arrested and Swamiji had offered himself for arrest. On this stage this matter was referred to the Privileges Committee. The Committee has brought forward two points. Firstly that the hon. Minister for Home Affairs had tried to shield the officers. Secondly the officers have failed in their duty of informing you about the arrest of an hon. Member of this House.

This report gives an indication of the methods of working of police officers in Delhi. An hon. Member is arrested and he is detained in the Police Station for hours together, but this fact is not conveyed to you. The officers have shown lack of responsibility.

I want to submit that it is not for the first time that the Delhi Police have done in this manner. Many noted personalities of Delhi were arrested under Section 107 and 151. The Delhi High Court was moved and it passed stricture against Delhi Magistracy. I want that the House should reprimand the hon. Minister for making a wrong statement. He should apologise.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन पर जो 22 मई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार किया जाये।"

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म. प. पुनः समवेत हुई।

THE LOK SABHA REASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN HOURS OF THE CLOCK

[श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए]
[Shai C. K. Bhattacharya *in the Chair*]

विशेषाधिकारी समितिजारी

(Motion re: first Report) **COMMITTEE PRIVILEGES-CONTD.**

पहला प्रतिवेदन

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The first Report of the Committee is befor the House. I congratulate the Committee for this Report. The privileges of the members in a democracy are of great significance. The Committee has gone into the whole question and has taken evidence from all concerned..

An hon. Member of this House was arrested and detained in Police station. This fact should have been conveyed to you. The Home Minister is also responsible for some

misunderstanding. Delhi Police is directly under him. He too tried to mislead the House. The District Magistrate has now offered unconditional apology to the Committee. The Home Minister should also apologise to the House and in future they should be careful in such matters. The Police should be given necessary instructions to be careful in this regard.

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : समिति के सामने जो तथ्य आये हैं उनमें तथा गृह-कार्य मंत्री के कथन में बहुत अन्तर है। मंत्री महोदय ने अधिकारियों की रिपोर्ट पर बहुत भरोसा किया है। पुलिस स्वामी जी को थाने ले गई थी। यह एक तथ्य है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को पहले अच्छी प्रकार देख लिया करें कि अधिकारियों की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है। मंत्रियों को वक्तव्य देने से पहले अच्छी प्रकार से देखभाल कर लेनी चाहिये।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Sir, it is a unanimous Report. I hope the House will adopt it. I want to point out two things. The attitude of the Delhi officials towards the people is not good. The Inspectors who came to tender evidence were tutored. I had mentioned this there also. The lawlessness and correption is on the increase because the behaviour of officials towards people is not proper, and people have lost confidence in police. The Home Minister should pay proper attention towards this. I request that this Report should be adopted and the Home Ministry should pay attention towards this.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं इस मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। सभा के एक सदस्य ने सभा में वक्तव्य दिया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था अथवा हिरासत में लिया गया था। गृह-कार्य मंत्री को इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिये था तथा अधिकारियों द्वारा बेढंगे रूप से की गई जांच पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। जब संसद के एक सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो पुलिस जनसाधारण के साथ किस प्रकार व्यवहार करती होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

कम से कम इन मामले में गृह कार्य मंत्री को क्षमा मांगनी चाहिये क्योंकि उन्होंने एक माननीय सदस्य के विरुद्ध व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य दिया है। इस समिति के प्रतिवेदन से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि अधिकारियों द्वारा किये गये कामों को उचित ठहराने के लिए सरकारी जांच से वास्तविक पर पर्दा नहीं डाला जाना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्य इस मामले में राजनीति को घुसेड़ रहे हैं। हम संसद सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। विशेषाधिकार समिति ने बहुत बातों पर विचार किया परन्तु उसे गृह-कार्य मंत्री अथवा गृह मंत्रालय के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली। इसलिए, सभा को समिति के प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्ष स्वीकार कर लेने चाहिये। यह मामला अब सन्तोषजनक ढंग से सुलझाया जा चुका है तथा हम समिति का प्रतिवेदन स्वीकार करते हैं।

श्री बलराज मधोक : हमने इस मामले में राजनीति लाना कभी नहीं चाहा है। केवल हम कुछ मामले इस सदन के समक्ष लाना चाहते थे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन पर, जो 22 मई, 1967 को सभा में पेश किया गया था, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री आ० ना० मुल्ला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 22 मई, 1967 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उस सभा के कई सदस्यों ने सभा में दिये गये उत्तरों में शुद्धि करने के बारे में सूचना दी हैं । माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने सभा में गलत जानकारी दी है ।

सभापति महोदय : यह मामला अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है ।

रेलवे आयव्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा-जारी

RAILWAY BUDGET 1967–68–GENERAL DISCUSSION-Contd.

श्री राजाराम (सेलम) : रेलवे के बारे में कहा जाता है कि यद्यपि उसने देश के लिए कुछ नहीं किया है तथापि दुर्घटनाओं में लोगों की हत्या करके जनसंख्या की समस्या हल की है । पिछले कुछ समय में रेलों पर बहुत ही रेलवे दुर्घटनायें हुई हैं । इस मास की 21 तारीख को हुई एक भयंकर दुर्घटना में लगभग 69 व्यक्ति मारे गये ।

इस आयव्ययक में कई मदों पर दर बढ़ाये गये हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसा कोई वर्ष नहीं था जिसमें यात्री किराये और भाड़े की दरें न बढ़ाई गई हों । अब मूल्य अधिकतम सीमा से बहुत अधिक बढ़ गये हैं और ऐसे समय में इन नई दरों से मुद्रास्फीति को अवश्य बढ़ावा मिलेगा तथा कठिनाइयां भी बढ़ेंगी ।

मैं इन स्थिति की तुलना मद्रास राज्य से करना चाहता हूं । वहां के परिवहन मंत्री ने बसों के किराये 1 पैसा प्रति मील कम कर दिये हैं और वह अधिक राजस्व भी वसूल कर रहे हैं । इसलिए, संसाधनों की स्थिति में सुधार करने का एकमात्र तरीका यही नहीं है कि किराये बढ़ाये जायें, यहां पहले ही मुद्रास्फीति है और अब वह और भी बढ़ेगी ।

रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ किया जाता है । दिल्ली और मद्रास के बीच डाइनिंग कार में बहुत बार भोजन नहीं मिलता है तथा लोगों को भूखे ही रहना पड़ता है । इसी प्रकार कई बार तृतीय श्रेणी में वातानुकूल करने की मशीनरी कार्य नहीं करती। जल की भी व्यवस्था उचित नहीं होती, उन सभी बातों पर विचार करना चाहिये, यह कमियां प्रस्थान के स्टेशनों पर ही दूर की जा सकती हैं ।

रेलवे मंत्रालय की सूचना के अनुसार सेलम–धर्मपुरी रेलवे लाइन जून में चालू की जा रही है । इसे बढ़ा कर बंगलौर तक किया जाना चाहिये अन्यथा इसे चालू रखने में आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी । ऐसी एक योजना भी है परन्तु मालूम नहीं, किन कारणों से इस बारे में विलम्ब किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जानी चाहिये ।

सेलम से मद्रास जाने वाली कई गाड़ियां हैं । उनमें से एक ब्ल्यू माउन्टेन एक्सप्रेस में, जो रात को 10 बज कर 10 मिनट पर चलती है, तीन शामिकाओं वाला एक डिब्बा जोड़ दिया जाना चाहिये ।

हम बहुत समय से मद्रास में वृत्ताकार रेलवे की मांग कर रहे हैं । अपेक्षाकृत कम धन लगाकर इस समय चालू कुछ लाइनों को उचित प्रकार से जोड़ा जा सकता है । रेलवे मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये । तिरुवेल्ली–कन्याकुमारी–त्रिवेन्द्रम लाइन बनाने से हजारों यात्री आकर्षित होंगे । मद्रास अर्कोणम् लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये । कोचीन एक्सप्रैस में डीजल इंजन लगाया जाना चाहिये । मयूरम जंक्शन तथा सेलम जंक्शन पर ऊपरी पुलों की व्यवस्था की जानी चाहिये । माननीय रेलवे मंत्री को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : The budget of the biggest industry in the country is under the consideration of the House. The success or the failure of the railways depends upon the progress achieved in the economic field.

The increase in the prices of the articles, which are needed for the railways, also affects the pace of progress of the railways. The price of iron and steel was Rupees one hundred in 1950–51 and it has gone to Rupees 225 in the year 1965–66. The increase in the salaries of the employees is 84 per cent and the increase in the price of coal is 81 per cent. On the other hand, the rise in fare and freight is only 48.7 per cent. The fares for small distances had not been increased so far, but now it has been done to meet the deficit. It is, however, clear that the increase in the fares and freights is much less than the increase in prices.

The number of railway accidents was minimum in the year 1965—66. Although there has been improvement in this regard, the accidents have affected the quantum of goods transported by the railways. When the accidents are frequent, the owners of goods regard road transport to be safer. These things are very important and if the position is improved, it can help the railways to compete with road transport. There is a tough competition to the railways. Out-agencies should be opened in more areas to secure more goods for railway transport.

Mail and Express trains are generally overcrowded. Alongwith the increase in railway fares, more trains should have been introduced or more bogies should be attached to the existing trains. Attention should also be paid to the matter of receiving the complaints of the passengers.

The population of towns is on the increase and the existing stations are less than the requisite number. In view of the increased population trucks and other vehicles have to wait for a very long time on the railway crossings.

In order to have a quicker and smoother flow of traffic, more overbridges and underbridges should be provided. Narrow gauge lines should be nationalised. This will increase the income of the railways.

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : रेलवे आय व्ययक देखने के बाद एक बार फिर हमारे देश के लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि कांग्रेस की नीति जनता विरोधी नीति है। इससे हमारे देश की समस्यायें हल नहीं हो सकतीं। तीन योजनाओं को काल पूरा हो जाने के बाद तथा देश के तथा कथित विकास पर करोड़ों रुपये का व्यय होने के बाद भी इस नीति से देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

रेलवे मंत्री ने बताया है कि रेलवे को इस वर्ष 31 करोड़ रुपये की हानि होगी। यह कमी पूरी करने के लिए मंत्री महोदय ने माल भाड़ा तथा किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, भाड़े की दरें ऐसी होनी चाहिये कि उसे सहन किया जा सके परन्तु रेलवे के इस सिद्धान्त की उपेक्षा की हैं। इससे रेलवे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं तथा जन-साधारण चाहता है कि कुछ राहत मिले। इसकी बजाय कि रेलवे उन्हें राहत दे, उसका बोझा और बढ़ा दिया गया है।

भर्ती के मामले में रेलवे जनता की बिलकुल कोई सेवा नहीं कर रही है। लम्बे समय तक कार्य करने के पश्चात् लोगों को अपनी सेवा के अन्तिम चरण में पदोन्नति दी जाती है। जैसा कि अब मंत्री महोदय ने बताया है, कमी को पूरा करने के लिए लोगों की पदावन्नति की जायेगी। इस आयव्यय से रेलवे कर्मचारियों के भाग्य में यही आया है।

मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें। भाड़े तथा किराये में वृद्धि करना बहुत गलत काम होगा। समझ में नहीं आता कि रेलवे को घाटा कैसे हो सकता है। कुप्रबन्ध के कारण ही रेलवे में उचित लाभ नहीं हो रहा है। कई मामलों में रेलवे अना-वश्यक व्यय कर रही है। उदाहरण के लिए सरकार कोयला खानों के मालिकों को कोयला का दाम अधिक दे रही है जबकि उसे कुछ अन्य खानों से कोयला सस्ता मिल सकता है। 4 अथवा 5 रुपये कम मूल्य मांगने वाली कोयला खानों को ठेका नहीं दिया गया है। विलम्ब शुल्क तथा उतराई शुल्क में करोड़ों रुपये की हानि हुई।

अप्रैल, 1966 से फरवरी, 1967 तक के अभिलेखों से मालूम हो सकता है कि झुन-झुनू वाला एण्ड ब्रादर्स से उतराई शुल्क 2,30,378,65 रुपये लेना था परन्तु रेलवे ने 1,67,498.43 रुपये की छूट दे दी। विलम्ब शुल्क की 34,725 रुपये की राशि शेष थी परन्तु 9,856 रुपये की छूट दे दी गई। रेलवे की बहुत बड़ी राशि इस तरह लोगों की जेबों में जा रही है और जनसाधारण को इस से कठिनाई हो रही है। आपको इन बातों की न्यायिक जांच करनी चाहिये। आपको मालूम नहीं कि रेलवे के बड़े अफसर सैलूनों द्वारा यात्रा करते हैं और इसके साथ ही यात्रा भत्ता भी लेते हैं।

छोटे स्टेशनों से छोटे कार्यालय बिना किसी कारण के स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कलकत्ता के चेनजिल से रेलवे कार्यालय हटाना चाहते हैं। प्रशिक्षण स्कूल

सियालदह से बदल कर धनबाद ले जाया जा रहा है। इसके लिए भवनों के निर्माण पर करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ते हैं।

बिलासपुर में कार्यालय निर्माण के लिये 12 करोड़ रुपये का काम है जिसमें से वालटेयर में 2 करोड़ रुपये का काम है और शेष काम मध्य प्रदेश राज्य में रायपुर और बिहार में है। अब उनका प्रस्ताव चीफ इन्जीनियर (निर्माण) और डी० बी० के० रेलवे के कार्यों को मिलाने का है। उन्होंने अब निर्माण कार्यालय को बिलासपुर से वालटेयर ले जाने का निश्चय किया है। वहां अधिकारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये पर्याप्त धन-राशि व्यय की जायेगी। मेरे विचार में ये क्वार्टर अधिकारियों को नहीं मिलेंगे बल्कि उन्हें परेशान किया जायेगा।

अब रेलवे लोको शैड को गोहाटी से भालेगाँव बदला जा रहा है जो केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले गौहाटी में भवन निर्माण का काम हुआ अब यही काम मरलेगाँव में होगा। यदि वे इस प्रकार निर्माण कार्य बढ़ाते न जायें तो उनकी जेबों में धन कैसे जायेगा। इसी कारण गार्डन रीच से प्रेस को हटाकर खड़गपुर ले जाया जा रहा है। इस प्रकार छोटे स्टेशनों से छोटे कार्यालय बिना किसी कारण के स्थानान्तरित किये जाते हैं। यदि इस प्रकार के तबादलों को रोका जा सकता हो तो काफी धन-राशि बच सकती है।

रेलवे प्रशासन में अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है। रेलवे बोर्ड में एक सतर्कता का निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, बहुत से उपनिदेशक, केवल सतर्कता विभाग में ही हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों में भी अधिकारियों की संख्या अत्यधिक है। क्या वे उन व्यक्तियों को पकड़ते हैं जो वास्तव में भ्रष्टाचारी है ? इस की बजाय छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जाता है जो थोड़ा सा कोयला उठा लेते हैं। मुझे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारी ने बताया था कि हम उच्च अधिकारियों को इसलिये नहीं पकड़ सकते क्योंकि उससे उनकी अपनी नौकरी को खतरा हो जाता है। एक बार रेलवे के एक बड़े अधिकारी के विरुद्ध एक मामला दायर किया गया। जब वास्तविक भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ लिया गया तो दिल्ली से निदेश मिला कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये। रेलवे मंत्री माल भाड़े के किराये बढ़ा सकते हैं परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते।

अब मैं रेलवे के कुप्रबन्ध को लेता हूं। एक बार जब हम कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे तो डाइनिंग-कार के प्रबन्धक ने हमें चाय नहीं दी क्योंकि उसके पास चीनी नहीं थी। जब इन डाइनिंग-कारों की व्यवस्था गैर-सरकारी ठेकेदारों के हाथ में थी तो सब काम ठीक चलता था और वे लाभ भी अर्जित करते थे परन्तु जब से रेलवे प्रशासन ने इन का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया है तो वे घाटे पर जाने लगीं, क्यों ? इसका कारण यह है कि डाइनिंग-कारों पर नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं रखा जाता। इसका दूसरा कारण यह है कि जो खाद्य वस्तुएं डाइनिंग-कार के लिये निर्धारित होती हैं, वे बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में पहुँच जाती हैं। जो मछली, मांस, सब्जियां जनता को दी जाती है वे बासी होती हैं जो तीन या चार दिन तक बिना रैफ्रिजेरेटर के रखी रहती हैं।

इसके अतिरिक्त डाइनिंग-कार में काम करने वालों को बिल्कुल आराम नहीं मिलता, उन्हें 24 घण्टे काम करना पड़ता है। यदि कोई बीमार पड़ जाये तो भी उसे छुट्टी नहीं मिलती।

इतना ही नहीं, मितव्ययता के नाम पर कितनी बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। जबकि रेलवे अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कितने ही डिवीजनों में अधिकारियों के पदों में वृद्धि की जा रही है जबकि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के पदों में कमी की जा रही है। केवल दक्षिण-पूर्व रेलवे में ही लगभग 6000 ऐसे पदों का या तो समर्पण कर दिया है या उनके पदों की अवनति कर दी गई है। मैं सभा का ध्यान इस ओर इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार कर्मचारियों की छटनी से लोगों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा। कर्मचारियों के काम करने के घण्टों का प्रश्न भी है। क्या आपको मालूम है कि इंजन ड्राइवर को क्या काम करने के लिये कहा जाता है ? जब सहायक स्टेशन मास्टर, गार्ड और ड्राइवर 20 घंटे काम करने के बाद और अधिक काम करने से इन्कार कर देते हैं तो उन्हें विलम्बित कर दिया जाता है और उन पर अवज्ञा का आरोप लगाया जाता है।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह सतर्कता स्क्वॉड को समाप्त कर दें क्योंकि उसका कोई विशेष उपयोग नहीं है। यही स्थिति सुरक्षा विभाग की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि गरीब रेलवे कर्मचारी, न कि रेलवे अधिकारी, अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। अधिकारियों की पदोन्नति आप करें, परन्तु इसके साथ रेलवे के अन्य कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। उन्हें अब तक अधिक मंहगाई भत्ता मिल जाना चाहिये था परन्तु गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों के नाम पर आपने ऐसा नहीं किया। आकस्मिक श्रमिक रेलवे का प्रमुख अंग है। वे रेलवे मार्ग को चालू स्थिति में बनाये रखते हैं परन्तु उन्हें सामान्य भत्ता भी नहीं दिया जाता। जो कुछ उन्हें मिलता है उसमें से भी वह कुछ रेलवे का अधिकारी को घूस के तौर पर दे देते हैं ताकि उन्हें दोबारा काम पर लगाया जा सके।

आपने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अन्तर्गत कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया है। इन व्यक्तियों पर साम्यवादी होने का आरोप लगाया जाता है। मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार के मामलों पर पुनः विचार करें। टी० टी० ई० कर्मचारियों को गाड़ी के साथ साथ चलने वाले कर्मचारियों के रूप में समझना चाहिये। उनकी यह मांग है कि चूंकि उन्हें गार्डों, ड्राइवरों के साथ यात्रा करनी पड़ती है और उन्हीं के साथ खाना खाना पड़ता है इसलिये उन्हें भी गाड़ी के साथ साथ चलने वाले कर्मचारी घोषित करना चाहिये। पहले गार्डों को ड्राइवरों से वेतन अधिक मिलता था, अब ड्राइवरों को अधिक मिलता है। इनके वेतन को बराबर ही क्यों नहीं कर दिया जाता। इस समय क्लर्क, वाणिज्य निरीक्षकों से अधिक वेतन पा रहे हैं। इसलिये वाणिज्य निरीक्षक के पद की पदोन्नति क्यों नहीं कर देते।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं रेलवे आयव्ययक का समर्थन करता हूं। रेलवे सब से बड़ा सरकारी उपक्रम है जिसमें 3,500 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। इस उपक्रम की कुल आय 2 करोड़ प्रति दिन है और इसमें 13½ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। परन्तु राजनीतिक दृष्टि से इसे घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो वर्षों में, चाहे बम्बई बन्द हो या पूना बन्द, या और किसी प्रकार की गड़बड़ हो, राजनीतिक आन्दोलन का यह लक्ष्य बना हुआ है। हमें सब राज्य-सरकारों से मिल कर कुछ ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिये जिससे ये सब बातें बन्द हो जायें।

दूसरी बात यह है कि इस सरकारी उपक्रम का खर्च बहुत बढ़ गया है। वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि के कारण भी इस खर्च में वृद्धि हुई है जैसे लोहे और इस्पात पर ही चालू वर्ष में रेलवे को चार करोड़ रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे। राजनीतिक उपद्रवों से उद्योग के प्रभावित होने के कारण भी सरकार की चिन्ता बढ़ी है। इसलिये इस समस्या का कोई और समाधान ढूंढना चाहिये।

गाड़ियों के विद्युतिकरण और डीजलयुक्त बनाने का कार्य तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक बिजली और डीजल के इन्जन तथा उनके पुर्जे देश में नहीं बनते। मैं विद्युतिकरण और डीजलयुक्त इन्जन बनाने के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु मैं यह चाहता हूं कि हमें अपने गाढ़े पसीने की कमाई को इन इंजनों को खरीदने के लिये खर्च नहीं करना चाहिये। कुछ समय बाद हमारे देश के युवक स्वयं इस प्रकार के इंजन बना सकेंगे। इस प्रकार मितव्ययता की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 11000 भाप के इंजनों में से 1400 शीघ्र ही बेकार हो जाने वाले हैं। इन भाप के इंजनों का सदुपयोग करना चाहिये।

जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है वे पहले से कम हो रही है। बहुत सी दुर्घटनाएं मानवीय भूलों के कारण होती हैं। इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि गेंग-मील को तीन से बढ़ा कर चार मील कर दिया गया है। इसके साथ ही गेंग के व्यक्तियों की संख्या भी नहीं बढ़ाई गई। इसलिये लाइनों की ठीक ढंग से देखरेख नहीं की जा सकती।

दूसरी बात अतिरिक्त पुर्जों जैसे ब्रेक, ब्लाक, सिलण्डर और रेल के डिब्बों के जोड़ने के कुण्डों के सम्बन्ध में है। मुझे ऐसा पता चला है कि अतिरिक्त पुर्जों के अभाव के कारण इंजन और डिब्बे मरम्मत के लिये वर्कशाप में भेजे जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय बाद ये पुर्जे खराब हो जाते हैं और इसी कारण दुर्घटनाएं होती हैं। प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि भण्डारों में कमी करनी चाहिये। परन्तु ऐसे महत्त्वपूर्ण पुर्जों की कमी नहीं होनी चाहिये।

जहां तक अन्तनगरीय रेलवे का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ वास्तव में अलाभकारी हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम इन लाइनों का पूरी तरह प्रसार नहीं करते। यदि हम इनका प्रसार करें तो ये निश्चय ही मितव्ययी सिद्ध होंगी।

अब मैं अपने राज्य के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। मैं जोगी घोपा स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी के पार एक उपरी पुल बनाना चाहिये और बड़ी लाइन को गोहाटी तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। ऐसा करने से इसका सम्बन्ध गारो पहाड़ियों से हो जायेगा। जिन्हें विभिन्न प्रकार की खनिज की खान के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

आसाम मेल में तीसरी श्रेणियों के डिब्बों की बहुत बुरी दशा है। बरौनी में की जाने वाली रिजर्वेशन के विषय में जितना कम कहा जाय, उचित होगा। इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। बरौनी में स्थिति इतनी खराब है क्योंकि वहां निरीक्षण के लिये कोई अधिकारी नहीं जाता। मैं अन्त में यह अनुरोध करूंगा कि इस लाइन पर कुछ और गाड़ियां चलाई जानी चाहिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापटनम) : मंत्री महोदय ने किराये बढ़ाने के लिये जो स्पष्टीकरण दिये हैं वे अधिक प्रभावशाली नहीं हैं। यदि रेलवे की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन या लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को देखा जाये तो पता चलेगा कि कितना खर्च बेकार का किया जाता है जो बचाया जा सकता है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि गत बीस वर्षों से यह पहली बार है कि रेलवे को हानि हुई है। क्या उन्होंने एक वर्ष के घाटे को पूरा करने के लिये स्थायी रूप से किराये बढ़ा दिये हैं ? यह एक अनुचित बात है।

वर्ष 1964–65 के लेखों से पता चलता है कि उस वर्ष 41 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। इसी प्रकार वर्ष 1965–66 और 1966–67 के दौरान भी बचत होगी। पहले अनिवार्य वस्तुओं को खरीदने के लिये भी कह दिया जाता है कि धन उपलब्ध नहीं है और वर्ष के अन्त में बचत दिखाई जाती है। लोक लेखा समिति ने ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की है जिनके लिये टेन्डर देने वालों को रियायत दी गई और बहुत बड़ी धन-राशि दी गई और उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अब दक्षिण केन्द्रीय जोन बना दिया गया है और यह ठीक ही हुआ है परन्तु इस जोन से वालटेयर और गुडूर डिविजनों को बाहर रखना उचित नहीं है। वाल्टेयर दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे तथा दक्षिण केन्द्रीय रेलवे का जंकशन है। अब क्योंकि डी० बी० के० रेलवे बन्द हो रहा है, इसलिये कर्मचारियों को अधिक असुविधा होगी, क्योंकि वे रेलवे के पृथक पृथक जोन से लिये गये हैं। अब उन्हें अपने अपने विभागों में जाने के लिये कहा जा रहा है जबकि उन्हें इस रेलवे में काम करते हुए 7–8 वर्ष हो गये हैं और उनके बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी असुविधा होगी। यदि कुछ ऐसा प्रबन्ध हो जाये कि उन्हें वालटेयर से जाना न पड़े तो यह प्रशंसनीय बात होगी। इससे उनके बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि डी० बी० के० रेलवे के कर्मचारियों को दक्षिण पूर्वी रेलवे में ले लिया जाय ताकि वे वालटेयर में ही रह सकें।

रेलवे की सुविधाओं के विषय में तो जितना कम कहा जाय, अच्छा होगा। मद्रास और कलकत्ता लाइनों पर गाड़ियां अधिक चलाई जानी चाहिये क्योंकि सब से अधिक भीड़ इन्हीं गाड़ियों पर होती है। मैं उस दिन की इन्तजार कर रहा हूं जब मैं विशाखापतनम से दिल्ली को गाड़ी पर आऊं और उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों।

इसी प्रकार हैदराबाद एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु इस स्टेशन पर भी सुविधाएं बहुत कम हैं। भोजन की व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। सफाई का तो नाम ही नहीं। जो वस्तुएं भोजन में दी जाती है वह शुद्ध नहीं होती, मतलब यह कि इनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। रेल गाड़ियों के साथ चलने वाले कन्डक्टरों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये। वातानुकूलित गाड़ियों में जो गद्दे रखे जाते हैं उन पर अच्छे तथा स्वच्छ कपड़ों के गलाफ होने चाहियें। खेद की बात है कि स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गाड़ियां समय पर चलती नहीं है। पूर्वी तट पर गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हैं। वहां पर डाक गाड़ियों की गति 18 मील एक घंटा है। गोदावरी पर रेल तथा सड़क का पुल बनना चाहिये।

काकीनाडा एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह है। उसे मुख्य लाइन के साथ मिलाया जाना चाहिये।

वाल्टेयर स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहियें। रेलवे विभागों में यदि अपव्ययता को समाप्त कर दिया जाये तो भाड़े आदि में वृद्धि की आवश्यकता ही न हो।

माल भाड़े तथा किराये में वृद्धि से सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। रेलवे मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह किराये तथा भाड़े आदि में वृद्धि न करें।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : Now that the fares and freight are going to be increased, I request. that more facilities should be provided–particularly to the third class passengers. More facilities should be provided at Kanpur Railway Station, where the train reaches at 6 or 7 in the morning.

A big part of revenue comes from third ciass passengers. About 86 per cent people travel in third class while only about 12 percent travel by second class or first class. Are we providing to the third class passengers the amenities in proportion to their revenue earnings ? It is not. This should be done. Thousands of acres of land is lying waste along the railways lines in our country. It should be utilized for agricultural purposes. The diferage of the Railways property should be stopped more vigorously. The Railway lines which were dismentled should be restored without further delay. I have found that drinking water is not available at small railway stations. This amenity must be provided The catering arrangement is not satisfactory at Railway stations. Necessary arrangement should be made in trains and at Railway stations. The railway line from Katihar to Brauni should be converted into a broad gauge. It will be very beneficial.

Healthy competition should be developed with the road transport. People think that sending of goods through railway is not safe. This impression should be done away with. Corruption is prevalent on a large of scale in Railways Vigilance Department should he streamlined. It should be under the Railway Board. This Department is very useful. It can prove very effective in checking corruption.

The problem of over-crowding is a big problem. The difficulty is that tickets are issued without keeping in view the capacity of trains. This can be seen from the fact that berths in trains are reserved weeks in advance. I suggest the more coaches should be attached with trains. It will ease the situation a great deal.

Passengers of third class should be provided more facilities.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The Railways suffer from many ills. We have been supplied a booklet entitled "A Review of the accidents on Indian Government Railways, 1965–66". This Book is self contradistory. It gives different figures in regard to the persons killed on Indian Railway.

There have been many committees for rooting out corruption from Railways The Ministers say that majority of the recommendations of there committees have been accepted but the result if before us. I can say that basic recommendations are not implemented. The recommendations about the length of line a permanent way Inspector is supposed to check has not been implemented. A white paper has been brought forward in regard to Railway safety. I challenge its authenticity. I think the members of the Railway Board and other high officials are responsible for Railways, going into loss. Railway Board should be abolished. It is doing precious little for the efficiency of Railways. Last year's Audit Report of Railways points out many deficiencies and failures of Railway Board. I suggest that the members of Railway Board who are responsible for this should be penalised suitably. Railway Board pays little attention to problems which are raised. The problems are very vital for the common man who travels by Railways. The saloons and luxurious bogies and other facilities provided to the Railway officers should be done away with. The saving thus resulted should be spent on the lower categories of employees who are responsible for running the railways. Higher allocations

have been made for providing accommodation facilities to officers. I would request the hon. Minister to pay more attention to the problems of the lower class in this respect.

It is a matter of regret that Government is paying no attention to the welfare of the people. Unions of the employees are being suppressed. Ten to fifteen office bearers of the workers Union in Estern Railway were dismissed because they demonstrated before the office of the General Manager. I would like to know whether holding of demonstration is a crime ? I can quote so many instances where Government have tried to disintegrate the Unions.

The conduct rules formulated for the workers are very much humiliating. Under the rules workers have to indicate to the administration whether any member of their family is connected with any political party. Such humiliating rules should not have found any place.

I will give few solid suggestions. Due share should be given to the workers in the management and their co-operation should be sought at every stage. They should also be associated with the vigilance organisation to detect the case of theft and corruption. A committee consists of Members of Parliament and other eminent people of country to go into whole affair of the railways.

श्री त्रिमला कांति घोष (संरायपुर) : रेलवे बजट में घाटे को पूरा करने के लिए मंत्री महोदय ने किराये तथा वस्तु भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। वर्तमान लागत को देखते हुए यह वृद्धि उचित ही है क्योंकि लोहा, इस्पात तथा कोयला आदि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। प्रशासन चलाने के व्यय में भी वृद्धि हुई हैं।

यह कहना ठीक नहीं है कि बिना टिकट यात्रा को रोककर कमियां को दूर कर तथा अवांछनीय व्यय को दूर कर बजट को संतुलित किया जा सकता है। यह एक समाजिक समस्या है और इसको उसी दृष्टिकोण से हटाया जाना चाहिए। परन्तु में इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि बढ़े हुए किरायों के साथ यात्रा अधिक सुविधाजनक बनाई जानी चाहिए। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अच्छे प्रतीक्षालयों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पीने के पानी की सप्लाई में सुधार किया जाना चाहिए। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए खाने पीने का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि नगरों के अन्तरनगरीय भागों में अधिक रेल गाड़ियां चलाई जानी चाहिए हावड़ा- बर्धवान के बीच और अधिक रेल गाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि स्वतन्त्रता के बीस वर्षों के पश्चात भी सभी रेलवे का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। हावड़ा और हुगली जिलों के बीच छोटी लाइन पर चलने वाली मारटिन रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इसकी स्थिति में भी सुधार आवश्यक है।

रेलवे मंत्री ने ब्रांच लाइनों के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे है। कुछ ब्रांच लाइनें अलाभप्रद हो सकती है परन्तु दूसरी ओर प्रतिरक्षा की दृष्टि में वे महत्वपूर्ण भी हो सकती है। इसलिए इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उद्योग में संकट होने के कारण रेलवे द्वारा माल के लाने लेजाने में भी कमी हुई है। वास्तव में अनुमान ही कुछ अधिक लगाये गये थे।

वर्तमान 'टाप हैवी' प्रणाली के रहते हुए रेलवे की अर्थ-व्यवस्था में जो स्थिरता आगई है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। परिवहन नीति तथा समवाय समिति के अनुसार 1950–51 में देश के कुल माल का 89 प्रतिशत माल रेल द्वारा लाया ले जाया जाता था परन्तु 1964-65 में यह 77 प्रतिशत रह गई हैं। 1950–51 में जहाँ रेलवे में कुल 827 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगी हुई थी वहाँ आज 3000 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। परन्तु इन सब के बावजूद सरकार इसको ठीक प्रकार से चलाने में असमर्थ रही है।

रेलवे भ्रष्टाचार का केन्द्र है तथा अपनी सेवाओं में अच्छी योजनाएं न बनाने तथा अपनी अदक्षता के लिए प्रसिद्ध है। यात्री किराये तथा माल भाड़े की वृद्धि से साधारण जनता पर ही अधिक भार पड़ेगा।

रेलवे अर्थ व्यवस्था में गतिरोध के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। रेलों तथा गाड़ियों के डिब्बों की मांग के न होने के कारण भिलाई तथा कलकत्ता के डिब्बे बनाने वाले कारखानों से कर्मचारियों को निकाले जाने की सम्भावना है। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। आजकल नई भर्ती पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इससे भी बुरी बात यह है कि सरकार इलैक्ट्रिक कप्यूटर लगाना चाहती है। हमारे जैसे देश में जहाँ कि जनशक्ति बहुत है ऐसी मशीने नहीं लगाई जानी चाहिए। यद्यपि वित्त मंत्री ने कहा है कि इनके लगाये जाने से कर्मचारियों की छटनी नहीं की जायेगी तथापि उनको और आगे उन्नति के अवसर नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि सरकार अपनी इस योजना पर जमी रही तो एक आन्दोलन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है। इन मशीनों से सबसे बड़ा खतरा यह है कि इनसे रेलवे गाड़ियों के खुफिया वहन का भी पता चल जाता है। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन मशीनों को न लगायें।

रेल गाड़ियों में भीड़ बहुत अधिक होने लगी है। इसका सब से अधिक प्रभाव तीसरे दर्जे के डिब्बों पर पड़ा है यदि किसी 100 यात्रियां की क्षमता वाले डिब्बे में 175 व्यक्ति हो तो रेलवे प्रशासन उसको अधिक भीड़ नहीं मानता। इस समय यात्रियों को कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है। देश के 7000 स्टेशनों के लिए केवल 12 रिटायरिंगरुम है। इसलिए मेरा निवेदन है अधिक प्रतीक्षालय तथा रिटायरिंगरुम बनाये जाना चाहिए। यात्रियों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहिए। रेलवे की यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है। चार दिनों में चार दुर्घटनाएं हो गई हैं।

वाराणसी के डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना लगाया है उसमें 75 प्रतिशत पुर्जे अमरीका से मंगाये जाते हैं। उन पुर्जों को जोड़कर इंजन तैयार किये जाते हैं। यदि हम डीजल इंजन चालू करेंगे तो इनको चलाने के लिए डीजल का भी आयात करना पड़ेगा। आंकड़ों से पता लगता है कि 31–3–1967 तक 377 डीजल इंजनों का आयात किया गया था। 1965–66 में 662,00 टन डीजल फयूल का आयात किया गया।

यदि युद्ध हो जाता है तो ईंधन और अन्य पुर्जों का सम्भरण बन्द हो जायगा और विदेशी पूंजीवादी इसका अनुचित लाभ उठायेंगे। और भारतीय रेलवे का काम ठप हो जायेगा। रेलवे के बिजली के डिब्बों पर अत्यधिक खर्च किया जा रहा है। यह बेकार का

खर्च है। इन डिब्बों में यात्रा वे करते हैं जिन्हें सारे दिन में दो रोटी तक उपलब्ध नहीं होती। परन्तु वे उनमें यात्रा इसलिये करते हैं क्योंकि अमरीकी पूंजीपतियों को उससे धन मिलता है। गाड़ियों में इतनी भीड़ होती है कि उपनगरीय जनता को कभी डिब्बों के अन्दर और कभी छत पर यात्रा करनी पड़ती है। यदि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई तो रेलवे को निकट भविष्य में विनाश का सामना करना पड़ेगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि माल भाड़े में वृद्धि से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा और हमने सोचा था कि माल भाड़े में वृद्धि नहीं की जायगी। परन्तु रेल यात्रा के किराये और माल भाड़े दोनों में वृद्धि कर दी गई।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

यदि रेलवे के अन्य खर्चों में बचत की जाती तो किराये बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी।

उड़ीसा राज्य में प्रदीप को मुख्य लाइन के साथ जोड़ने–कलकत्ता–मद्रास लाइन पर की अनवरत रुप से भोग रही हैं। प्राक्कलन समिति के 91 वें प्रतिवेदन में कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में अधिक प्रसार नहीं किया जो उन क्षेत्रों के विकास के लिये अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध में उसी प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर, 1962 में रेलवे बोर्ड, परिवहन विभाग और राज्य के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें यह निश्चित किया गया था कि इस लाइन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें।

मंत्री महोदय ने अलाभकारी लाइनों को हटा देने का उल्लेख किया था परन्तु ऐसा करते हुए उन्हें स्थानीय जनता की यातायात सम्बन्धी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिये। यह बात छोटी लाइनों के बारे में अधिक आवश्यक है। वास्तव में इन लाइनों पर चल रही गाड़ियों के 50 या 60 वर्ष पुराने इंजनों और डिब्बों को बदलने की आवश्यकता है। ऐसा करने के बाद देखना चाहिये कि ये लाइने लाभप्रद हैं या नहीं।

जहां तक रेलवे के नवीन निर्माण कार्यों का सम्बन्ध है, दक्षिण पूर्वी रेलवे को इसका बहुत कम अंश मिला है। इस सम्बन्ध में तलचर को रूड़केला के साथ मिलाने का काम किया जाना चाहिये और इसके बाद प्रदीप पत्तन को मद्रास–कलकत्ता में मुख्य लाईन से मिलाने का काम किया जाना चाहिये।

डीजल से चलाई जाने वाली गाड़ियों में इन्जन की खराबी प्रायः हो जाती है और इसके फलस्वरूप गाड़ियां देर से पहुँचती हैं। इसलिये इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

समय सारिणी में मास में एक बार परिवर्तन करने से जनता को बहुत असुविधा होती है क्योंकि ऐसा करते हुए जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार के परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य जनता की सुविधा होना चाहिये।

जहाँ तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है मैं यह कहूँगा कि रेल–कर्मचारियों के व्यापारिक कार्य और परिवहन कार्य को मिलाना नहीं चाहिये। यह तो दुर्घटनाओं का एक कारण है। इसी प्रकार कर्मचारियों से अधिक काम लेने के कारण भी दुर्घटनाएं होती है। उन्हें पर्याप्त आराम मिलना चाहिये। दुर्घटनाओं को रोकने का यह सर्वोत्तम साधन है।

श्री शिवप्पा (हसन) : रेलवे एक बहुत बड़ा उद्योग है, इससे तो अत्यधिक लाभ होना चाहिये परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस आयव्ययक से निर्धन व्यक्ति पर अधिक बोझ पड़ा है। किराये बढ़ा दिये गये हैं परन्तु सुविधाओं का नाम ही नहीं। बिना सुविधाओं में वृद्धि के किराये बढ़ाना अनुचित है। यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। इस प्रकार किराये और रेल भाड़े में वृद्धि निराधार है। तीसरे दर्जे के डिब्बों में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यह बात मंत्री महोदय भी भली भांति जानते हैं। यदि उन्होंने कभी इस दर्जे में यात्रा की होती तो वह ये किराये कभी न बढ़ाते क्योंकि तीसरे दर्जे में केवल निर्धन जनता यात्रा करती है। यह वृद्धि क्योंकि न्याय संगत नहीं है इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें।

जहाँ तक सुविधाओं का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक गाड़ी के साथ एक चलता फिरता अस्पताल होना चाहिये जिससे यात्रियों को लाभ होगा और विशेषकर दुर्घटनाओं के समय तो ये अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। शासक दल को चाहिये कि वे जनता की सुविधाओं के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं।

यह खेद की बात है कि हसन–मंगलोर परियोजना के लिये लगभग 2,50,00,000 रुपये की धन–राशि निर्धारित की गई है। मैं इस परियोजना के महत्व पर अधिक प्रकाश नहीं डालना चाहता क्योंकि मंत्री महोदय स्वयं उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस परियोजना की प्रगति नगण्य है जबकि इसकी प्रगति आरम्भ से ही तेज होनी चाहिये थी। जो धन–राशि इस परियोजना के लिये निर्धारित की गई है वह तो अर्जित भूमि को क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिये ही अपर्याप्त होगी। 23 करोड़ रुपये के प्राक्कलन में से केवल 2½ करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस परियोजना अत्यधिक लाभ होने की आशा है। इस दृष्टि से इस परियोजना को बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिये था, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस काम में बहुत देरी हो गई है। हमें आशा थी कि इस आयव्ययक में कद्दूर–सकलेशपुर को मिलाने से सम्बन्धित परियोजना को सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु हमें खेद है कि ऐसा नहीं किया गया।

हमें यह भी आशा थी कि बंगलौर और मैसूर के बीच की लाइन पर बिजली लगा दी जायेगी, परन्तु वह भी नहीं हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण मैसूर राज्य की अवहेलना कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में हजारों टन नारियल और सफेद मिट्टी उपलब्ध होने वाली है जिसका निर्यात किया जायेगा और जिसके फलस्वरुप विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी। इस पहलू पर किसी ने विचार ही नहीं किया। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

आधे घंटे की चर्चा

Half an Hour Discussion

पाकिस्तान को अमरीका हथियारों की सप्लाई

SUPPLY OF U. S. ARMS TO PAKISTAN

अध्यक्ष महोदय : भाषण देने के बजाय केवल प्रश्न पूछे जायें या किसी बात में संदेह हो तो पूछा जाय ताकि हम आधे घण्टे में इस चर्चा को समाप्त कर सकें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): 22 मई, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के विषय में बताया है कि पाकिस्तान को अतिरिक्त पुर्जे सम्भरण करने का एक एक मामले पर पृथक-पृथक रूप में विचार किया जायेगा । इन मामलों में शान्ति को बनाये रखने और तनाव को कम करने के विचार से इन पर विचार किया जायेगा ।

मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अतिरिक्त पुर्जे देने से किस प्रकार शान्ति को बनाये रखने और तनाव को कम करने में सहायता मिल सकती है और विशेषकर जबकि एक बार युद्ध हो चुका है । अभी कुछ ही दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में श्री स्वर्णसिंह ने यह बात मानी है कि उपरोक्त पुर्जों के सम्भरण के कारण पाकिस्तान को हमारी सीमाओं पर गोलाबारी करने के लिये उत्तेजना मिली है । इससे स्पष्ट है कि इन पुर्जों के सम्भरण के कारण हमारी सीमाओं पर स्थिति और बिगड़ी है ।

हथियारों के सम्भरण के स्थगन के विरुद्ध पाकिस्तान ने प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने की धमकी दी थी । इस सम्बन्ध में "हिन्दू" दिनांक 28–4–66 में छपे समाचारों का हवाला दिया जा सकता है । पाकिस्तान ने अमरीका को रावलपिंडी में अमरीकी सैनिक प्रतिष्ठानों को बन्द करने की धमकी दी थी । इसलिये अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देने का निश्चय किया । पश्चिम जर्मनी ने जो हथियार इरान को दिये थे, वे पाकिस्तान पहुंच गये । इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने रोषपत्र भेजा था, परन्तु उसका कोई उत्तर मिला था या नहीं; मुझे इस बात में संदेह है । अमरीका के मित्र देश अब भी पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं । पाकिस्तान को जब सुरक्षा सम्बन्धी खर्च कम करने के लिये कहा गया तो उनका उत्तर यह था "पाकिस्तान सुरक्षा पर 12 प्रतिशत और खर्च करेगा । पाकिस्तान ने विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने का भी निश्चय किया ।

अध्यक्ष महोदय : वह सारी स्थिति स्पष्ट तो कर रहे हैं परन्तु आधे घन्टे का सारा समय तो वही ले लेंगे । दो या तीन सदस्यों को अभी बोलना है और मंत्री महोदय ने फिर उत्तर भी देना है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह कहना कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने से तनाव कम होगा या उससे शान्ति स्थापित होगी गलत बात है । अमरीका विअतनाम में क्या कर रहा है ? पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी अमरीकी साम्राज्यवादियों पर है । पाकिस्तान को अमरीकी हथियार दिये जाने से हमारी सुरक्षा को खतरा है । जब अमरीका को बताया गया कि पाकिस्तान चीन से हथियार ले रहा है तब भी वे चुप रहे । चीन की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में दो आयुध क रखाने स्थापित किये जा रहे हैं । अमरीका भी उनको हथियार दे रहा है ।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें अब विदेश नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिये। क्या अब भी हम इस प्रकार के अमित्रतापूर्ण कार्यों के विरूद्ध केवल रोषपत्र भेज कर ही संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं ? भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिये था कि हमारा मित्र देश कौन सा है और शत्रु कौन है। क्या यह सत्य नहीं है कि रूस हमारा मित्र देश है। अमरीकी गुट ने हमारी धरती पर जो आक्रमण किया है तो हम उसके उत्तर के रूप में रूस के साथ पूर्ण रूप से सैनिक गठबन्धन क्यों न कर लें। अमरीका चीन के नाम पर पाकिस्तान को अड्डा बनाकर उसका प्रयोग भारत के विरुद्ध कर रहा है। मुझे विश्वास है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने पर अमरीका ने कोई आपत्ति नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने पर्ची चिट भेजी है केवल उन्हें बोलने का अवसर दिया जायेगा। मैंने इस चर्चा को 6 बजे समाप्त कर देना है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The reason of tension between India and Pakistan is the supply of arms by America to Pakistan. This is an unfriendly act on the part of America. I am, however, not in favour of alliances which is pleaded by Shri Banerjee. We should look to our own interest or our country's interest, and we should frame our foreign policy accordingly. America wants that we should depend on her for all times to come in all matters viz. Technicians, food, arms, exports. America has penetrated in our life to the extent that we have started thinking whether we are Indians in the real sense. We should be self-reliant and I want to know the steps taken by the Government in this direction. We should tell America straightaway that supply of arms to Pakistan is an unfriendly act and India will no longer tolerate it. If America does not agree, we should make them realise by our behaviour and action. Is it not a fact that Pakistan has not only recouped its arms strength as a result of resumption of American Aid instead they have got much more arms ?

I would also like to know whether U. S. A. has supplied all the arms promised by them at the time of Chinese invasion. I have come to know that not even half of the promised quantity of arms has been received as compared to the supplies received by Pakistan.

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : ताशकंद उद्घोषणा के पश्चात अमरीका का जो रवैया रहा है उससे सभी परिचित हैं। हमारी आपत्ति के बावजूद अमरीका ने पाकिस्तान को पुर्जों आदि के रूप में सहायता देना आरम्भ कर दिया है। इससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो गया है। क्या सरकार ने अमरीका की इस कार्यवाही की निन्दा करने के लिये इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद में उठाया है ? क्या सरकार बिना किसी देश के साथ गठबन्धन किये, किसी अन्य देश से हथियार लेने के बारे में विचार कर रही है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अब अमरीका पाकिस्तान को अतिरिक्त पुर्जों के रूप में पुनः हथियार दे रहा है। पाकिस्तान को सैनिक गठबन्धन का सदस्य होने के नाते कितनी सहायता मिल चुकी है और इस सहायता की शर्तें क्या हैं ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में सदा के लिये तनाव बना रहे। क्या हमने उन देशों को इस बात से सहमत करने के लिये कोई राजनयिक प्रयास किये हैं कि वे पाकिस्तान को सशस्त्र सहायता न दें जिनके हित का हम ध्यान रखते रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमने अमरीका से अपील भी की और रोष-पत्र भी भेजे कि वे पाकिस्तान को सहायता न दें और पाकिस्तान सही ढंग से बर्ताव करे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे यदि हम पर कोई आक्रमण कर देता है, तो हम अकेले न रह जाएं।

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्री बनर्जी ने मेरे वक्तव्य को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने तो कहा था कि पाकिस्तान के हम पर आक्रमण के कारण हम अपनी सुरक्षा सम्बन्धी खतरे के बारे में अमरीका को बार-बार बताते रहे हैं और यह भी बताते रहे हैं कि अमरीका के हथियार देने के निश्चय से केवल पाकिस्तान को ही लाभ होगा। इसके बाद मैंने अमरीका का दृष्टिकोण बताया था जो श्री बनर्जी ने उद्धृत किया था। हमने अमरीकी दृष्टिकोण से पूर्ण असहमति व्यक्त की थी और हमने यहाँ भी और वाशिंगटन में भी विरोध प्रकट किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका सदा भारत और पाकिस्तान को बराबर मानता रहा है। वे कहते हैं कि हम आपको भी उतनी ही सहायता देंगे जितनी हम पाकिस्तान को देंगे। वे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की सारी सैनिक शक्ति अमरीकी हथियारों के कारण बनी हुई है अब अतिरिक्त पुर्जे देकर वह पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को पुनः बढ़ा रहा है।

हमने जो पुर्जे खरीदे हैं वह या तो ब्रिटेन से या रूस से खरीदे हैं। यदि अमरीका भारत और पाकिस्तान को बराबर मानता है तो इससे पाकिस्तान को ही लाभ है। पाकिस्तान तो चीन से हथियार ले रहा है जो अमरीका का शत्रु है और अब अमरीका से वह अतिरिक्त पुर्जे ले रहा है। इससे पाकिस्तान की सैनिक शक्ति फिर उतनी ही हो जायेगी जितनी भारत-पाकिस्तान युद्ध से पूर्व थी। हमने अमरीका को ये अब बातें बताई हैं। अमरीका के इस आश्वासन के बावजूद कि अमरीकी हथियार भारत के विरुद्ध नहीं प्रयोग किये जायेंगे, पाकिस्तान ने कच्छ के संघर्ष में इनका प्रयोग किया और हमने इसकी सूचना अमरीका को दी थी। सितम्बर, 1965 के युद्ध में भी पाकिस्तान ने अमरीकी हथियारों का खुल कर प्रयोग किया। यह तो हमारे जवानों की वीरता और हमारे राष्ट्र के दृढ़ संकल्प के कारण हमने उस युद्ध को जीता। हमने इस सारी स्थिति से अमरीका को अवगत कराया है।

एक ओर अमरीका कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की दौड़ समाप्त होनी चाहिये जबकि दूसरी ओर वे पाकिस्तान को अतिरिक्त पुर्जे दे रहे हैं। इसलिये हम भी अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : चीन के आक्रमण के समय हथियार देने का जो वचन दिया गया था उसका क्या हुआ ?

श्री मु० क० चागला : वे हमें मिल गये थे। परन्तु वे केवल पहाड़ों पर युद्ध लड़ने के लिये ही थे। इन परिस्थितियों में हमारे लिये केवल एक ही रास्ता है और वह यह कि हमें आत्म-निर्भर होना चाहिये। पाकिस्तान सारे यूरोप से हथियार खरीद रहा और जब कभी हमें पता चलता है कि कोई देश पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो हम तत्काल उस देश के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करते हैं जैसे हमने जर्मनी के मामले में किया। जर्मनी ने कुछ हवाई-जहाज इरान को बेचे थे जो बाद में पाकिस्तांन को मिल गये और हमने इस मामले में जर्मनी से बातचीत की।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We came to know about this only after the event. What our Ambassador has been doing earlier ?

श्री मु० क० चागला : जब हमें पता चला, तो इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई । हमें पश्चिम जर्मनी ने बताया कि ये हवाई जहाज पाकिस्तान को मरम्मत के लिये भेजे गए थे और वे मरम्मत के बाद इरान लौट जायेंगे ।

कुछ देशों में हथियार बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं । बहुत से यूरोपीय देशों में हथियार बनाने वाली गैर-सरकारी फर्में हैं और वे इन्हें किसी भी देश को बेच सकते हैं । ऐसे देशों से यदि पाकिस्तान हथियार लेता है तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने हितों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्य करते रहें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्दार) : यदि अमरीकी आश्वासनों के बावजूद यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है तो क्या अमरीका भारत की सहायता करेगा ?

श्री मु० क० चागला : अमरीका ने इस प्रकार के आश्वासन दिये परन्तु हमारा इन पर विश्वास नहीं । यदि हम शक्तिशाली होंगे तो हम अपनी सुरक्षा कर सकेंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 30 मई, 1967 / जयेष्ठ 9, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjorned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 30, 1967 Jyaistha 9, 1889 (Saka).